आषाढ़ कृष्ण पक्ष-8, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 03 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म।प्र।/4-474/2024-26

भोपाल
08 जुलाई 2026 बुधवार

आज का मौसम
31.0 अधिकतम
24.2 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

अयोध्या कांड की असली कहानी चढ़ावे की चोरी नहीं है...!

अयोध्या की असली कहानी शायद चढ़ावे की चोरी नहीं है। असली कहानी उस चोरी के बाद शुरू होती है। एसआईटी के गठन से, उसकी प्रारंभिक जांच की कथित जानकारियों के मीडिया तक पहुंचने से, खबरिया चैनलों पर अचानक मचे शोर से और अंतिम जांच रिपोर्ट आने से पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की कवायद से। इन घटनाओं को अलग-अलग देखिए तो सब सामान्य लगेगा। लेकिन इन्हें जोड़कर देखिए। सवालों की ऐसी श्रृंखला खड़ी होती है, जिसका जवाब न उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, न खबरिया चैनलों पर चख-चख करते एंकर पूछ रहे हैं और न तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक।

प्रसंगवश

राजेश सिरोठिया

9 नवंबर 2019 के ऐतिहासिक अयोध्या फैसले के अनुपालन में केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग के सामने कह चुकी है कि ट्रस्ट न तो केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व में है, न ही उनके प्रशासनिक नियंत्रण में और न सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर है। यानी ट्रस्ट स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है। तो पहला सवाल सीधा है- ऐसे स्वायत्त ट्रस्ट के आर्थिक और प्रशासनिक मामलों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी किस वैधानिक आधार पर गठित की? चोरी हुई है तो मुकदमा दर्ज हो। पुलिस जांच करे। आर्थिक अपराध है तो विशेषज्ञ आर्थिक अपराध जांच एजेंसी को मामला सौंपा जाए। लेकिन एसआईटी में शामिल अधिकारियों की बड़े आर्थिक अपराधों, फोरेंसिक ऑडिट, बैंकिंग फ्रॉड और जटिल वित्तीय लेन-देन की जांच में विशेषज्ञता क्या है? और एसआईटी चोरी की जांच करते-करते ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे तक कैसे पहुंच गई? यदि उसकी प्रारंभिक जांच में सीईओ जैसी व्यवस्था की जरूरत बताई गई तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किसी जांच दल को केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वायत्त ट्रस्ट का प्रशासनिक मॉडल सुझाने का अधिकार किस कानून ने दिया?

अब घटनाक्रम देखिए...

एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जांच पूरी नहीं हुई। दोष किसका है और चोरी आपराधिक मिलीभगत का परिणाम थी या व्यवस्थागत विफलता का, इसका अंतिम निर्धारण बाकी है। लेकिन उससे पहले ही ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चयन के लिए कमेटी तक गठित कर दी गई। जांच पूरी होने से पहले इलाज कैसे तय हो गया? अगर अंतिम रिपोर्ट यह कहती है कि चोरी कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत या किसी आपराधिक गिरोह का काम थी और ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में कोई बुनियादी खामी नहीं थी, तब भी क्या सीईओ नियुक्त होगा? यदि हां, तो क्या सीईओ की नियुक्ति का फैसला जांच के अंतिम निष्कर्षों से पहले ही कहीं तय हो चुका था?

और अब इस कांड की असली अंतर्कथा..

एसआईटी की प्रारंभिक जांच की कथित जानकारियां मीडिया तक कैसे पहुंचीं? यदि रिपोर्ट आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हुई थी तो उसके कथित निष्कर्ष और सिफारिशें चुनिंदा खबरिया चैनलों और अखबारों को किसने बताईं? एसआईटी के किसी सदस्य ने? सरकार के किसी अधिकारी ने? ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी ने? या किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे जांच की दिशा के साथ उसके मीडिया नैरेटिव को भी नियंत्रित करने में दिलचस्पी थी? किसने लीक किया? किसके इशारे पर किया? और क्यों? क्या मकसद सच बताना था या अंतिम रिपोर्ट आने से पहले एक खास धारणा तैयार करना? एक और संयोग देखिए। देश के नामी-गिरामी खबरिया चैनलों पर उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के विज्ञापनों की बाढ़ और लगभग उसी दौर में अयोध्या के चढ़ावा कांड की खबरों का सैलाब। कल तक विपक्ष जिन्हें 'गोदी मीडिया' कहता था, उनमें से कई चेहरे अचानक 'जन आस्थाओं से खिलवाड़' के नाम पर ट्रस्ट के महासचिव को कठघरे में खड़ा करने लगे। उनके सुर सरकार विरोधी और वाम झुकाव वाले मीडिया मंचों से मेल खाने लगे।

आखिर ऐसा क्या बदल गया?

तथ्य? पत्रकारिता? वैचारिक प्रतिबद्धताएं? या अयोध्या की इस कहानी के पीछे कोई ऐसी कहानी है, जिसकी पटकथा अभी देश के सामने आई ही नहीं? चढ़ावे की चोरी गंभीर अपराध है। करोड़ों रामभक्तों की आस्था और उनके चढ़ावे से खिलवाड़ करने वाला कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि चढ़ावा किसने चुराया। सवाल यह भी है कि एसआईटी किस वैधानिक अधिकार से बनी? उसकी जांच की सीमा क्या थी? प्रारंभिक जांच की कथित बातें किसने मीडिया तक पहुंचाईं? अंतिम रिपोर्ट से पहले सीईओ की जरूरत किसने तय की? और एक स्वतंत्र तथा स्वायत्त ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की इतनी जल्दी क्यों है?

क्योंकि कई बार असली कहानी जांच रिपोर्ट में नहीं होती।

असली कहानी यह है कि जांच रिपोर्ट आने से पहले उसे कौन लिख रहा है ?

सवाल है- अयोध्या में जांच चोरी की हो रही है या चढ़ावे के बहाने राम मंदिर ट्रस्ट पर नियंत्रण की नई पटकथा लिखी जा रही है...?

न्यूज विंडो

बंगाल में बच्ची से रेप-मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर का एक आरोपी प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रभास को गोली लगी।

बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला नौटियाल पर मुकदमा दर्ज

गोपेश्वर। बद्रीनाथ धाम में दान-चढ़ावे में हेराफेरी प्रकरण के आरोपित वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल के विरुद्ध बद्रीनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात प्रमोद नौटियाल को मंगलवार को निलंबित किया गया था।

जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति भी गठित की गई है। यह समिति 15 दिन में शासन को रिपोर्ट देगी।

आपत्तिजनक ऐड को लेकर मेटा ने कहा- हमने पहले ही हटा दिए

नई दिल्ली। सरकार ने पिछले सप्ताह इंस्टाग्राम पर बच्चों के आपत्तिजनक ऐड को लेकर नोटिस जारी किया था। सरकार ने मेटा के अधिकारियों को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर तलब किया था। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने इसे लेकर अब सफाई दी है और कहा कि हम पहले से ही बच्चों से जुड़े मामलों को लेकर संवेदनशील हैं। हमारा सिस्टम पहले ही ऐसे कंटेंट की पहचान करके उसे पहले ही प्लेटफॉर्म से हटा देता है।

कोचिंग विवाद में खान सर की बेल पर सुनवाई पूरी, फैसला 10 को

पटना। कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के दौरान फायरिंग मामले में आरोपित फैजल खान उर्फ खान सर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। पटना सिविल कोर्ट के जिला जज रूपेश कुमार देव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत आदेश 10 जुलाई को सुनाएगी। कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय के एंटिसिपेटरी बेल पर याचिका दाखिल की गई थी।

युद्ध का खतरा... अमेरिका का ईरान के 80 ठिकानों पर हमला

सीजफायर टूटा, फिर बरसे बम

वॉशिंगटन/तेहरान, एजेंसी

पश्चिम एशिया में कुछ दिन पहले हुए सीजफायर चल रही शांति एक बार फिर टूट गई है। अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिका की एयरस्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया।

ईरानी मीडिया के मुताबिक, सीरिक, केश्म द्वीप और बंदर अब्बास में कई धमाके हुए और कुछ जगहों पर आग लग गई। इसके जवाब में ईरानी सेना ने बहरीन और कुवैत में अमेरिका सैन्य ठिकानों पर 85 से ज्यादा टारगेट्स हिट करने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे क्षेत्र में नए युद्ध की आशंका पैदा कर दी है।

अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि मंगलवार को ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी हितों पर हुए हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई। दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून और हाल में हुए संघर्षविराम का उल्लंघन बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

» ईरान का पलटवार - बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक का दावा

अमेरिका ने ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास पर हमला किया।

तनाव बढ़ने के साथ ही खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जबकि समुद्री परिवहन कंपनियां होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की लगातार समीक्षा कर रही हैं। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए यहां किसी भी तरह का व्यवधान वैश्विक बाजारों को तुरंत प्रभावित करता है। इसी आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। राजनयिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है।

दुनिया की नजर अगले कदम पर

पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति बेहद निर्णायक मोड़ पर है। यदि अमेरिका और ईरान दोनों जवाबी सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं तो यह टकराव व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसमें खाड़ी के कई अन्य देश भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होंगे। सबसे बड़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर है। यदि यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे ईंधन की कीमतों, महंगाई और वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हालात युद्ध की ओर बढ़ते हैं या कूटनीति एक बार फिर तनाव कम करने में सफल होती है।

चार दिनों की तेजी के बाद फिसला सेंसेक्स

अमेरिका-ईरान तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। चार कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में रहे। सेंसेक्स 550 अंक नीचे

कारोबार कर रहा है। निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी को लेकर रही। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ने, महंगाई पर दबाव बनने और उद्योगों की लागत बढ़ने की आशंका है। इसका असर ऑटो, एविएशन, पेंट और तेल पर निर्भर अन्य क्षेत्रों के शेयरों पर देखने को मिला, जबकि तेल उत्पादन से जुड़ी कुछ कंपनियों के शेयरों में मजबूती दर्ज की गई।

बड़ी सफलता

शोपियां में लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर गनई ढेर, शव बरामद

शोपियां, एजेंसी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में चल रहे आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकवादी मारा गया है। लश्कर के टॉप कमांडर जाकिर गनई ढेर हुआ है। उसका शव बरामद कर लिया गया है। आतंकी के पास हथियार भी मिले हैं। एक आतंकी की तलाश जारी है। अभी इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की पक्की खुफिया जानकारी मिलने के बाद चार दिन पहले यह आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन शुरू किया गया था। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक ऑपरेशन जारी था। मारे गए आतंकवादी की पहचान हो गई है।अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों को 3 जुलाई को मीमंदर इलाके के एक घने बाग में लगे निगरानी कैमरों में देखा गया था।

पीथमपुर उद्योग क्षेत्र को करोड़ों की सौगात

भोपाल, दोपहर मेट्रो

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि-पूजन कर रहे हैं। चीन की अग्रणी बहुराष्ट्रीय निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी गुआंग्शी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार मध्यप्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पीथमपुर में

स्थापित होने वाला नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 272 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता विकसित की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का निर्माण किया जाएगा।

दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी वायुसेना बना भारत

नई दिल्ली, एजेंसी

दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना रखने वाले देशों की लिस्ट सामने आई है। 'वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ़ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट' यानि WDMMA ने दुनियाभर की वायुसेनाओं की रैंकिंग जारी की है। इसमें बताया गया है कि भारतीय वायुसेना, चीन की वायुसेना के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है। WDMMA ने दुनिया के 103 देशों की 129 एयर मिलिट्री यूनिट की तुलना की है और 48 हजार 82 एयरक्राफ्ट पर नजर रखी है।

WDMMA की रैंकिंग में दुनिया की अलग अलग एयर फोर्स यूनिट की लड़ने की कुल क्षमता का आकलन किया गया है। यह रेटिंग सिर्फ एयरक्राफ्ट की कुल संख्या के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हमला करने और बचाव करने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर TVR स्कोर तैयार किया गया है।

वायुसेनाओं की रैंकिंग: अमेरिका की वायुसेना को 242.9 स्कोर दिया गया है और पहले नंबर पर रखा गया है। यूएस एयरफोर्स के बाद दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को रखा गया है, तीसरे नंबर पर रशियन एयर फोर्स और चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी है।

मेट्रो एंकर

राज्यपाल बोलीं - लव मैरिज का विरोध नहीं लेकिन आत्मनिर्भर होने के बाद ही आगे बढ़ें युवा

घर से भागकर प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां, बच्चे पहुंचते हैं बालगृह: आनंदीबेन

लखनऊ, एजेंसी

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से भावनाओं में बहकर जीवन के बड़े फैसले नहीं लेने की अपील करते हुए कहा कि आजकल कई लड़के-लड़कियां घर से भाग जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों में कई बार लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन बाद में हालात बदलने पर बच्चों को अपनाने वाला कोई नहीं होता और वे बालगृहों तक पहुंच जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ती है। राजयपाल ने युवाओं से कहा 'ऐसा पराक्रम आप लोग मत करिए। दूर रहिए इन पराक्रमों से।' उन्होंने पहले आत्मनिर्भर बनने और उसके बाद ही विवाह करने की सलाह दी।

लखनऊ में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं से संवाद के दौरान

राज्यपाल ने कहा कि वह प्रेम विवाह की विरोधी नहीं हैं, लेकिन शादी से पहले आर्थिक रूप से सक्षम होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही विवाह का निर्णय लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की सामाजिक या पारिवारिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति समाज और परिवार, दोनों के लिए चिंता का विषय है।

अपने बेटे का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब वह पढ़ाई के लिए बेंगलुरु गया था तो उन्होंने उससे कहा था कि यदि उसे कोई लड़की पसंद हो तो वह परिवार को बताए, शादी कराने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा अवसर नहीं आया, लेकिन यदि किसी युवक या युवती को जीवनसाथी पसंद आता है तो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आर्थिक रूप से सक्षम बनने के बाद ही विवाह का निर्णय लेना अधिक उचित होता है। उन्होंने कहा कि जीवनसाथी चुनना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी निभाने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है।

सुरक्षित माहौल मिले

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में निर्माण कार्य केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि उपयोगिता और सुविधा को ध्यान में रखकर किए जाएं। साथ ही छात्रावासों में आधुनिक रसोई और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आरओ प्लांट लगाने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी है।

आज का कार्टून

भोपाल में 200 करोड़ से बनेगा काउंटर टेररिज्म सेंटर, एनएसजी की तर्ज पर तैयार होंगे 250 कमांडो

सिंहस्थ-2028 से पहले एमपी को मिलेगा सुरक्षा का अभेद्य कवच

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

2028 के सिंहस्थ से पहले भोपाल में 200 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक काउंटर टेररिज्म सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में मध्य प्रदेश पुलिस के 250 विशेष कमांडो तैयार किए जाएंगे, जो आतंकवादी घटनाओं, बंधक संकट, आपदा प्रबंधन और वीवीआईपी सुरक्षा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में अधिकारियों को परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

वर्तमान में मध्य प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ता के तहत 50 सदस्यीय काउंटर टेररिज्म ग्रुप कार्यरत है, जिसकी संख्या बढ़ाकर 250 की जाएगी। यह केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र की तर्ज पर विकसित होगा। इसमें एटीएस, एसटीएफ, एसएएफ और क्यूआरटी के जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में हाल के वर्षों में सक्रिय हुए कई कट्टरपंथी और देशविरोधी मॉड्यूल को देखते हुए इस परियोजना को राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सिंहस्थ और संवेदनशील जिलों पर रहेगा विशेष फोकस

वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व और बड़े धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशिक्षण प्राप्त कमांडो की तैनाती भोपाल, इंदौर और अन्य संवेदनशील जिलों में की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें तत्काल एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जा सकेगा। कमांडो बल वीवीआईपी सुरक्षा और विशेष अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश पुलिस के 1,164 से अधिक जवानों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसे अब और व्यापक बनाया जाएगा।

किन जवानों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

प्रस्तावित केंद्र में एटीएस, एसटीएफ, एसएएफ और क्विक रिस्पॉन्स टीम के जवानों को आधुनिक आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कमांडो को बंधक मुक्ति अभियान, क्लोज कॉम्बैट, शहरी युद्ध, वीवीआईपी सुरक्षा, विस्फोटक निष्क्रिय करने और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों में दक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न जिलों की विशेष पुलिस इकाइयों को भी आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों की पुलिस इकाइयों को भी यहां प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा सकेगी।

क्यों जरूरी हुआ काउंटर टेररिज्म सेंटर

मध्य प्रदेश को लंबे समय तक शांति का टापू माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई संदिग्ध और देशविरोधी मॉड्यूल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों और नेटवर्क की जांच के मामले सामने आए हैं। ऐसे में किसी भी बड़े आतंकी हमले, बंधक संकट या संवेदनशील आयोजन के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित कमांडो बल की जरूरत महसूस की गई। यही वजह है कि सरकार ने स्थायी काउंटर टेररिज्म सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है।

तीन साल में भोपाल में 34 करोड़ की साइबर ठगी, केवल 10 फीसदी रकम ही हो सकी वापस

6 राज्यों के साइबर ठगों के निशाने पर मप्र साइबर सेल के लिए चुनौती बना नेटवर्क

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

मप्र और विशेष रूप से भोपाल देशभर में सक्रिय साइबर ठगों के संगठित नेटवर्क के निशाने पर हैं। बीते तीन वर्षों में अकेले भोपाल में करीब 34 करोड़ रुपए की साइबर ठगी दर्ज हुई, लेकिन बदलते अपराधी तरीकों और अलग-अलग राज्यों में फैले नेटवर्क के कारण पुलिस पीड़ितों को महज 10 प्रतिशत रकम ही वापस दिला सकी है।

जांच में सामने आया है कि ठग फर्जी दस्तावेजों पर पूर्वोत्तर राज्यों की सिम का उपयोग करते हैं, जबकि कॉल सेंटर और गैंग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड से संचालित होते हैं। ठगी की रकम ड्रॉपर खातों में जमा कराकर उसे कई राज्यों में ट्रांसफर और एटीएम के जरिए निकाल लिया जाता है। साइबर अपराधी हर महीने नया ट्रेंड अपनाते हैं। फिलहाल बिजली बिल अपडेट, प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, शेयर ट्रेडिंग और फर्जी निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच भोपाल में बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 5.55 लाख रुपए और एक अन्य व्यक्ति से 64,800 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।

ऐसे काम करता है ठगों का नेटवर्क

साइबर अपराधियों ने राज्यों के आधार पर अपनी जिम्मेदारियां तय कर रखी हैं। सबसे पहले फर्जी दस्तावेजों पर पूर्वोत्तर राज्यों से सिम कार्ड खरीदे जाते हैं। इसके बाद विभिन्न राज्यों में बैठे कॉल सेंटर लोगों को फोन कर झांसे में लेते हैं। ठगी की रकम सीधे ड्रॉपर खातों में जमा कराई जाती है और कुछ ही मिनटों में उसे दूसरे खातों या एटीएम के जरिए निकाल लिया जाता है। अपराध कई राज्यों में बंट जाने से जांच लंबी हो जाती है और अपराधी आसानी से सबूत मिटा देते हैं।

हर महीने बदल रहा ठगी का तरीका

साइबर अपराधी अब एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रहते। कभी बिजली बिल अपडेट, कभी बैंक केवाईसी, तो कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने के नाम पर लोगों को फंसाया जाता है। कई बार खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस, सरकारी एजेंसी या निवेश सलाहकार बताकर कॉल किए जाते हैं। लोगों की छोटी-सी लापरवाही उन्हें बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या ओटीपी साझा करने से बचना चाहिए।

बिजली बिल अपडेट के नाम पर लाखों रुपए की हुई ठगी

भोपाल में हाल ही में बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 5.55 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित को मोबाइल पर कनेक्शन काटने की चेतावनी वाला संदेश भेजा गया था। आरोपी ने खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताकर लिंक भेजा और बैंकिंग जानकारी हासिल कर ली। अगले दिन खाते से लाखों रुपए निकल गए। इसी तरह एक अन्य मामले में 64,800 रुपए की ठगी सामने आई है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

लिफ्ट मांगने वाले नाबालिग ने व्यवसायी को लूटा, हमला किया

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

परवलिया सड़क थाना क्षेत्र में एक दुग्ध व्यवसायी की इंसानियत उस समय भारी पड़ गई, जब रास्ते में लिफ्ट मांगने वाले एक नाबालिग ने सुनसान जगह पर ले जाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपित ने व्यवसायी के गले और हाथ पर ताबड़तोड़ वार कर लूट की कोशिश की। घायल व्यवसायी ने सूझबूझ दिखाते हुए जेब में रखे रुपये दूर फेंक दिए, जिसके बाद आरोपित रकम समेटकर मौके से भाग निकला।

गंभीर रूप से घायल व्यवसायी किसी तरह नजदीकी अस्पताल पहुंचा और अपने बेटे को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और महज पांच घंटे के भीतर आरोपित को पकड़ लिया। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई राशि भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार, परवलिया गांव निवासी सुनील उर्फ बब्लू पाल दुग्ध व्यवसाय करते हैं। उनका बेटा पंकज पाल न्यूजेल रोड स्थित आइटी पार्क की एक कंपनी में नौकरी करता है। देर रात करीब साढ़े आठ बजे सुनील

अपने बेटे को लेने बाइक से आइटी पार्क जा रहे थे। इसी दौरान गांव के पास एक किशोर ने उनसे लिफ्ट मांगी। मानवता के नाते उन्होंने उसे अपनी बाइक पर पीछे बैठा लिया। आरोपित ने उनसे रुपये देने की मांग की करीब तीन किलोमीटर आगे संधुखेड़ी जोड़ के पास पहुंचने पर किशोर ने पेशाब करने का बहाना बनाकर बाइक रुकवाई। जैसे ही सुनील रुके, आरोपित ने अचानक चाकू निकालकर उनके गले पर वार कर दिया। सुनील ने खुद को बचाने का प्रयास किया तो दूसरा वार उनके हाथ पर लगा। इसके बाद आरोपित ने उनसे रुपये देने की मांग की। अपनी जान बचाने के लिए सुनील ने जेब में रखे करीब 4,800 रुपए सड़क किनारे दूर फेंक दिए। आरोपित रुपये उठाकर मौके से भाग निकला, जबकि घायल सुनील वहीं गिरे रहे।

आरजीपीवी पेपर चोरी कांड में खुली सुरक्षा की पोल परीक्षा नियंत्रक डॉ. अर्चना अतिरिक्त दायित्वों से मुक्त

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में बीटेक चौथे सेमेस्टर (एआईएमएल) के प्रश्नपत्रों के नौ सीलबंद लिफाफे चोरी होने के मामले में गठित जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। जांच में सामने आया कि परीक्षा से जुड़े अत्यंत गोपनीय प्रश्नपत्र ऐसे कक्ष में रखे गए थे, जहां विद्यार्थियों और अन्य लोगों का नियमित आना-जाना लगा रहता था।

रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा नियंत्रक डॉ. अर्चना तिवारी को उनके सभी अतिरिक्त दायित्वों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। जांच समिति जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट कुलपति प्रो. आलोक शर्मा को सौंपेगी, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय होगी। जांच में यह भी पाया गया कि प्रश्नपत्रों की अलमारी की चाबी असुरक्षित दराज में रखी गई थी और गोपनीय सामग्री को सीसीटीवी निगरानी वाले स्ट्रांग रूम में रखने जैसी मूलभूत सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया गया था।

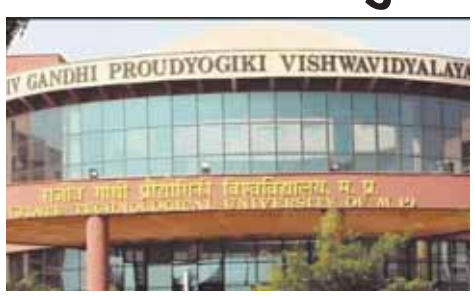

अभाविप ने उठाई निलंबन और सख्त कार्रवाई की मांग

प्रश्नपत्र चोरी मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय परिसर में करीब पांच घंटे तक प्रदर्शन किया। परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की। संगठन का कहना है कि केवल जिम्मेदारियों से मुक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिन अधिकारियों की प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, ताकि पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कर सकें।

सार्वजनिक कक्ष में रखे गए थे गोपनीय प्रश्नपत्र

जांच समिति के अनुसार प्रश्नपत्र जिस कक्ष में रखे गए थे, उसका उपयोग केवल परीक्षा शाखा तक सीमित नहीं था। उसी कक्ष में अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी संचालित होती थीं, जिससे विद्यार्थियों और कर्मचारियों का लगातार आना-जाना बना रहता था। जिस अलमारी में प्रश्नपत्र रखे गए थे, उसकी चाबी भी सुरक्षित स्थान पर नहीं रखी गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी संवेदनशील सामग्री को केवल सीसीटीवी निगरानी वाले सुरक्षित स्ट्रांग रूम में ही रखा जाना चाहिए था, जहां सीमित और अधिकृत कर्मचारियों को ही प्रवेश मिले।

18 और 19 जुलाई को नई प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक

रामराजा की नगरी से बजेगा चुनावी बिगुल ओरछा में होगा भाजपा का शक्ति प्रदर्शन

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यसमिति की पहली बैठक 18 और 19 जुलाई को ओरछा में आयोजित होगी। रामराजा सरकार की नगरी में होने वाली इस दो दिवसीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन के भविष्य के एजेंडे और चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में 106 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति, 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष और प्रकोष्ठ संयोजक शामिल होंगे। इसमें बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए संगठनात्मक रोडमैप तैयार किया जाएगा।

विपक्ष के गढ़ में सेंध लगाने पर रहेगा फोकस

प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का प्रमुख उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत बनाना है। 'हर बूथ, सबसे मजबूत' अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और कमजोर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ बढ़ाने की रणनीति बनाई जाएगी। हाल ही में घोषित कार्यसमिति में डॉ. मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों और विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियों के बंटवारे पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

बेटियों को गोद में मिल रही पहचान, बेटों को स्कूल तक इंतजार

भोपाल। राजधानी में बेटियों को लेकर परिवारों की सोच तेजी से बदल रही है। अब माता-पिता नवजात बेटियों का जन्म के दो-तीन महीने के भीतर ही आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ताकि उन्हें लाड़ली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। शहर के आधार केंद्रों के अनुसार पिछले छह महीनों में छह माह से कम उम्र के 227 बच्चों के बने आधार कार्डों में 176 बेटियां और 51 बेटे शामिल रहे।

गौतमनगर के शिवालय मंदिर में चोरी, देर रात शटर खोलकर दानपेटी ले उड़े चोर

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

गौतमनगर थाना क्षेत्र स्थित शिवालय मंदिर में चोरों ने देर रात दानपेटी चोरी कर ली। वारदात 5-6 जुलाई की दरमियानी रात की बताई जा रही है। मामले में मंदिर समिति के उपाध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने मंदिर में लगे शटर को खोलकर अंदर प्रवेश किया और वहां रखी दानपेटी उठाकर फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मंदिर के शटर पर ताला नहीं लगाया जाता था, जिसका फायदा उठाकर आरोपित आसानी से अंदर पहुंच गए। घटना की जानकारी अगले दिन मंदिर पहुंचने पर समिति के सदस्यों को लगी,

जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपितों की तलाश की जा रही है। साथ ही दानपेटी में मौजूद नकदी का भी आकलन किया जा रहा है।

मेट्रो एंकर | डी-कंजेशन पॉलिसी के तहत 6 शहरों में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर, गूगल मैप के डेटा से तय होगा ट्रैफिक

जाम से मिलेगी मुक्ति, एमपी में ट्रैफिक का नया ब्लूप्रिंट तैयार

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने डी-कंजेशन पॉलिसी पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के छह प्रमुख शहरों में एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे शहरों के व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा और यात्रा का समय घटेगा। राजधानी भोपाल में लाउखेड़ी से निगम विसर्जन घाट तक 3.7 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में भी परियोजनाओं पर काम जारी है। इन परियोजनाओं की खासियत यह है कि इनके डिजाइन तैयार करने से पहले गूगल मैप के

जरिए पीक ऑवर ट्रैफिक, वाहनों की संख्या, सड़क क्षमता और दुर्घटना रिकॉर्ड का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। भविष्य के यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर का डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है।

इन 6 शहरों की बदलेगी तस्वीर

डी-कंजेशन पॉलिसी के पहले चरण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा को शामिल किया गया है। जबलपुर में एक एलिवेटेड कॉरिडोर पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, जबकि भोपाल और ग्वालियर में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर और उज्जैन में नए कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो चुका है और रीवा में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन परियोजनाओं से शहरों के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक जाम में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

गूगल मैप बताएगा कहां और कितना बनेगा कॉरिडोर

एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से पहले ट्रैफिक के वैज्ञानिक अध्ययन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए गूगल मैप और डिजिटल ट्रैफिक डेटा का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा हर घंटे के ट्रैफिक फ्लो, पीक ऑवर जाम, सड़क की क्षमता और दुर्घटना के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसके आधार पर तय किया जाता है कि किस स्थान पर एलिवेटेड कॉरिडोर सबसे अधिक प्रभावी होगा और उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। इससे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद से बनेगा ट्रैफिक मॉडल

प्रदेश में बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर के डिजाइन में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जा रहा है। परियोजनाओं का तकनीकी डिजाइन न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से तैयार कराया जा रहा है। डिजाइन तैयार करते समय सड़क सुरक्षा, भविष्य के यातायात दबाव और शहरी विस्तार को ध्यान में रखा जा रहा है। विभाग का लक्ष्य केवल जाम कम करना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की परिवहन जरूरतों के अनुरूप आधुनिक और सुरक्षित शहरी यातायात व्यवस्था विकसित करना है।

सौर ऊर्जा पर बैटरी का पहरा, बढ़ सकते हैं बिजली के बिल

भोपाल। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नया मसौदा जारी किया है, जिसके तहत बड़ी सोलर कंपनियों के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों को वर्ष 2026-27 से अपनी कुल खरीद का 1.5 प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा भंडारण वाली सौर परियोजनाओं से लेना होगा, जिसे 2029-30 तक बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बैटरी सिस्टम पर बढ़ने वाला अतिरिक्त खर्च अंततः बिजली दरों और एफसीए के जरिए उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल सकता है।

ई-अटेंडेंस मामला: फैसले पर रियायत देने के मूड में नहीं सरकार, मंत्री बोले-

दिनभर मोबाइल चलाते हैं टीचर, फिर हाजिरी लगाने में क्या दिक्कत

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने के फैसले पर सरकार किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के हालिया बयान के बाद भी शिक्षक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। मंत्री ने साफ कहा है कि जब शिक्षक दिनभर मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो ई-अटेंडेंस लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं, शिक्षक संगठनों का कहना है कि वे ई-अटेंडेंस के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसे न्यायसंगत और संवेदनशील तरीके से लागू किया जाए। साथ ही सरकार शिक्षकों के निजी मोबाइल, इंटरनेट और सिम के उपयोग पर भी स्पष्ट नीति बनाए। दो दिन पहले बैतूल प्रवास के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ई-अटेंडेंस लागू करने में कोई समस्या नहीं है।

उन्होंने कहा, जब शिक्षक दिनभर मोबाइल चलाते हैं तो ई-अटेंडेंस लगाने में क्या प्रॉब्लम है?÷ मंत्री ने बताया कि जहां नेटवर्क की समस्या है, वहां सरकार समाधान के प्रयास कर रही है और ऐसे स्थानों पर पदस्थ शिक्षकों की गरिमा और व्यावहारिक कठिनाइयों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों करीब 1,000 जगहों पर नेटवर्क संबंधी दिक्कत सामने आई थी, लेकिन उन जगहों पर पदस्थ किसी भी टीचर की सैलरी नहीं काटी गई। सरकार का दावा है कि तकनीकी समस्याओं के कारण किसी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

शिक्षक संघ बोला- वेतन काटना और दंडात्मक कार्रवाई अनुचित

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने ई-अटेंडेंस को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशों पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है। संघ ने मांग की है कि 1 जुलाई 2026 को जारी वह आदेश जिसमें ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर वेतन कटौती तथा संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है उसे तत्काल निरस्त किया जाए।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री राकेश गुप्ता एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष विनोद कुमार पुनी ने कहा कि विभाग खुद स्वीकार कर चुका है कि प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में ई-अटेंडेंस सफलतापूर्वक दर्ज हो रही है और ज्यादातर जिलों में इसकी सफलता 94 से 95 प्रतिशत तक है। इसके बावजूद शेष तकनीकी कारणों से पैदा समस्याओं के लिए शिक्षकों को दोषी ठहराकर वेतन काटना उचित नहीं है।

व्यावहारिक-तकनीकी और मानवीय पक्षों की अनदेखी | ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डीके सिंगौर ने ई अटेंडेंस को लेकर कहा- यदि सरकार ई-अटेंडेंस जैसी तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है, तो इसके मकसद पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन, जिस स्वरूप में ई-अटेंडेंस लागू की जा रही है, उसमें अनेक व्यावहारिक, तकनीकी और मानवीय पक्षों की अनदेखी दिखाई देती है।

मशीन के आधार पर गैर हाजिर मान लेना गलत

केवल मशीन की उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को गैरहाजिर मान लेना और बिना उसका पक्ष सुने वेतन काटने जैसी कार्रवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। सिंगौर का कहना है कि शिक्षक का दायित्व केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं होता। उसे अनेक प्रशासनिक एवं शासकीय कार्य भी करने पड़ते हैं। कई बार विभागीय बैठकों, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, परीक्षा संबंधी कार्य, निर्वाचन दायित्व, विद्यार्थियों के हित में सामुदायिक समन्वय और विद्यालय की जरूरी व्यवस्थाओं के लिए विद्यालय परिसर से बाहर भी जाना पड़ता है।

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0: मुख्यमंत्री साझा करेंगे टेक्नोलॉजी विजन

भोपाल बनेगा टेक्नोलॉजी निवेश का नया हब, 13 को जुटेंगे देश- विदेश के दिग्गज

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 13 जुलाई को राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 ¬ जीसीसी, डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर , डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर प्रदेश को देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास का रोडमैप प्रस्तुत करेंगे। वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर निवेश, नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की साझेदारियों पर चर्चा करेंगे।

मध्यप्रदेश बन रहा निवेशकों की पहली पसंद

उद्योग-अनुकूल नीतियां, विश्वस्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन के कारण मध्यप्रदेश तेजी से निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। राज्य सरकार तकनीकी उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दे रही है। यही कारण है कि आईटी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उद्योगों में प्रदेश लगातार नई संभावनाएं तलाश रहा है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 को प्रदेश के तकनीकी और औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन से नए निवेश, रोजगार के अवसर और आधुनिक तकनीकी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मध्यप्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए देश के प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा।

पहले दो कॉन्क्लेव से मिला शानदार निवेश

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के पहले दो संस्करण प्रदेश के लिए निवेश और रोजगार के लिहाज से बेहद सफल रहे हैं। पहले कॉन्क्लेव में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 75 हजार रोजगार के अवसर सृजित हुए। वहीं दूसरे संस्करण में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ, जिससे करीब 48 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। तीसरे संस्करण का लक्ष्य इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई तकनीकी परियोजनाओं को प्रदेश तक लाना है।

देश-विदेश की कंपनियां होंगी शामिल

कॉन्क्लेव में देश और विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों, उद्योग संगठनों, निवेशकों और नीति विशेषज्ञों की भागीदारी होगी। सीटीआरएलएस डेटासेंटर्स, केन्स टेक्नोलॉजीस, फुजियामा पावर और न्योबोल्ट लिमिटेड जैसी अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होकर निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर संचालक, डेटा सेंटर डेवलपर्स और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा करेंगे।

जिम्मेदारों ने चार महीने तक दबाए रखा मामला

निगम में अब 14.69 लाख टैक्स घोटाला आरोपी कर्मचारियों की सेवा समाप्त नहीं

भोपाल, दोपहर मेट्रो

भोपाल नगर निगम में अब 14.69 लाख रुपए का प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स घोटाला सामने आया है। ताज्जुब की बात ये है कि इस मामले को जिम्मेदारों ने चार महीने तक दबाए रखा। इससे निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घोटाला नेशनल लोक अदालत के दौरान किया गया था। इस दौरान 106 फर्जी रसीदें काटकर लाखों रुपए हड़प लिए गए। जिम्मेदार अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी मार्च में ही मिल गई थी। उस दौरान दो अस्थायी कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आ गई थी। इसके बावजूद मामला चार महीने तक फाइलों में दबा रहा। 5

जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई। दोनों आरोपी जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन नगर निगम ने अब तक उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की हैं। एफआईआर के अनुसार 14 मार्च 2026 को वार्ड-33 के वार्ड प्रभारी रघुवीर तिवारी की यूजर आईडी से 106 फर्जी प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर रसीदें जारी की गईं। इनमें 14 लाख 69 हजार 798 रुपए टैक्स जमा होना दर्शाया गया, जबकि बैंक खाते के मिलान में गड़बड़ी सामने आई थी।

आधे टैक्स में रसीद का झांसा

जांच में सामने आया कि वार्ड-24 के कंप्यूटर ऑपरेटर शिराज उलहक और योजना शाखा में पदस्थ मोहम्मद समीर खान ने पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। दोनों संपत्ति मालिकों को आधी राशि में टैक्स जमा कराने का झांसा देते थे। वार्ड-24 की ऑपरेटर नाहिदा के माध्यम से उन्होंने वार्ड-33 के प्रभारी की यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल किए, फर्जी रसीदें जारी कीं और लोगों से वसूली गई रकम हड़प ली।

ऑनलाइन टैक्स सिस्टम भी कठघरे में

इस मामले ने नगर निगम के ऑनलाइन टैक्स सिस्टम की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वार्ड की यूजर आईडी का इस्तेमाल दूसरे वार्ड में कर 106 फर्जी रसीदें जारी हो गईं। ऐसे में पूरे सिस्टम का तकनीकी ऑडिट और अन्य वार्डों के रिकॉर्ड की जांच की जरूरत महसूस की जा रही है।

टैक्स भरने वालों को ही फिर बकायादार बना दिया

जिन भवन स्वामियों ने आरोपियों को टैक्स की राशि देकर रसीदें प्राप्त कर ली थीं, उनके खातों में दोबारा वही टैक्स बकाया दर्ज कर दिया गया। यानी, जिन लोगों ने भुगतान किया, उन्हें ही फिर से बकायादार बना दिया गया। दूसरी ओर, गबन की राशि आरोपियों से वसूलने की कार्रवाई अब तक शुरू नहीं हुई है। मामले में अपर आयुक्त अंजू अरुण कुमार ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिजली व्यवस्था पर साइबर हमलों का बढ़ता खतरा

एमपी ट्रांसको ने कर्मियों को दिया डिजिटल सुरक्षा का मंत्र

भोपाल, दोपहर मेट्रो

डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। खासकर बिजली जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के शक्ति भवन मुख्यालय में साइबर सिक्योर 2026 अभियान के तहत व्यापक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य साइबर पुलिस के विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को आधुनिक साइबर खतरों, ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों और डिजिटल सुरक्षा के प्रभावी उपायों की विस्तृत जानकारी दी।

साइबर पुलिस ने बताए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के तरीके

कार्यक्रम का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक, राज्य साइबर पुलिस उमाकांती आर्मो ने किया। उन्होंने विशेषज्ञों की टीम के साथ एमपी ट्रांसको के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने, मोबाइल एप्स का सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के दौरान डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी और सोशल इंजीनियरिंग जैसे नए साइबर अपराधों के बारे में विस्तार से बताया गया। विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को यह भी समझाया कि संदिग्ध कॉल, फर्जी लिंक, नकली ई-मेल और अनजान वेबसाइटों से किस प्रकार दूर रहना चाहिए। साथ ही डिजिटल लेनदेन करते समय अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मंत्री भूरिया

भोपाल। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें एक सुरक्षित, सकारात्मक एवं प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों के भीतर छिपी रचनात्मक प्रतिभा को सही मंच देना समाज और सरकार दोनों की साझी जिम्मेदारी है।

मंत्री भूरिया महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित जवाहर बाल भवन, भोपाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक प्रतियोगिताओं के गरिमामय समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। उन्होंने विभिन्न रचनात्मक विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री भूरिया ने बच्चों की अद्भुत और बहुमुखी प्रतिभा की जमकर सराहना की।

प्रदेशभर का पहला कॉलेज बना SGSITS

इंदौर में अब हिंदी माध्यम से होगी इंजीनियरिंग बीटेक सिविल ब्रांच से की गई सत्र की शुरुआत

इंदौर, दोपहर मेट्रो

ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (स्त्रस्ढ्ढञ्जस्) इंदौर में पहली बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करवाई जाएगी। इसकी शुरुआत 2026-27 शैक्षणिक सत्र से बीटेक सिविल ब्रांच से की गई है। ऐसा करने के पीछे असल वजह यह है कि देशभर में अधिकांश निर्माण स्थलों पर मजदूरों से हिंदी या स्थानीय भाषा में ही संवाद करना पड़ता है। मगर कई बार इंजीनियर्स को निर्माण से जुड़ी जानकारी मजदूरों को देने में दिक्कतें

आती हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करवाने से इंजीनियर उन्हें डिजाइन, सुरक्षा नियम और कार्य की प्रक्रिया आसानी से समझा सकेंगे।

उधर कोर्स में छात्र के लिए चार साल पढ़ने की बाध्यता नहीं होगी। प्रथम वर्ष में छात्र को इस तरह पढ़ाया जाएगा कि वह आईटीआई के ड्राफ्ट्समैन बराबर काम कर सके।

सिर्फ दो छात्रों ने लिया प्रवेश, काउंसलिंग प्रक्रिया जारी

हिंदी माध्यम में बीटेक सिविल ब्रांच पाठ्यक्रम का प्रस्ताव एआईसीटीई से मंजूर हो चुका है। इसमें 60 सीटें रखी गई हैं, जिसमें पहले चरण की काउंसलिंग में 35 सीटें आवंटित की गई थीं, लेकिन विद्यार्थियों की रुचि पाठ्यक्रम में कम नजर आ रही है। इसके चलते पहले चरण की काउंसलिंग संपन्न होने तक महज दो विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। हालांकि इसमें अभी प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

नई शिक्षा नीति के तहत मिलेंगे क्रेडिट पॉइंट

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को एंट्री और एग्जिट करना आसान होगा। छात्र चाहें तो पहले वर्ष या द्वितीय वर्ष तक पढ़ाई कर पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ सकते हैं। इस बीच नौकरी कर दोबारा कोर्स में विद्यार्थी प्रवेश ले सकेगा। खास बात यह है कि एनईपी में पाठ्यक्रम में अंकों की बजाय विद्यार्थियों का मूल्यांकन क्रेडिट पर किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की पढ़ाई के लिए निर्धारित क्रेडिट पॉइंट रखे गए हैं। विद्यार्थियों को इन मापदंडों पर खरा उतरना होगा। अधिकारियों के मुताबिक इस पाठ्यक्रम को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है, जिसमें छात्र भारत के परंपरागत मंदिर, महल और अन्य संरचनाएं व पारंपरिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

स्वच्छ मध्यप्रदेश
हम सबकी जिम्मेदारी

मेरे प्रिय प्रदेशवासियो,

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर मध्यप्रदेश में स्वच्छता को एक जन-आंदोलन बनाया गया है। विगत वर्षों में आप सभी के सहयोग से हमने स्वच्छता के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू हो चुका है, जिसमें जन-प्रतिनिधियों, निकायों, संस्थानों एवं नागरिकों के लिए कचरा प्रबंधन हेतु दायित्व नियत किए गए हैं। उक्त नियम केवल नगरीय निकायों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य के सभी विभागों में लागू किए गए हैं, जिनमें नगरीय क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे को भी समेकित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का परिपालन एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका सफल क्रियान्वयन केवल शासकीय प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि राज्य के प्रत्येक नागरिक एवं प्रतिष्ठान को इस कार्य में अपनी भूमिका निभानी होगी।

आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपनी दिनचर्या में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करें -

- आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम किसी भी प्रकार का कचरा, न तो खुले में फेकेंगे और न ही जलाएंगे।
- अपने घर, गली, मोहल्ले, शहर एवं प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने में सक्रिय योगदान देंगे।
- घर से निकलने वाले कचरे को चार प्रकार से अलग करके (गीला, सूखा, सैनिटरी एवं स्पेशल केयर) केवल कचरा वाहन को देंगे।
- कचरे के री-यूज़ और री-सायकल को बढ़ावा देंगे, जैसे- होम कम्पोस्टिंग, पुराने कपड़े, किताबें, अन्य उपयोगी वस्तुओं को फेकेंगे नहीं, बल्कि RRR (Reduce, Reuse, Recycle) केंद्रों में जमा करेंगे।
- कचरा कम करने के लिए छोटी-छोटी आदतों जैसे- अपना झोला और पानी की बोतल साथ रखेंगे तथा वस्तुओं का अधिकतम पुनर्प्रयोग आदि को अपनाएंगे।
- साथ ही समस्त नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि हर घर, दुकान और झुग्गी बस्ती से नियमित रूप से कचरा संग्रहण हो।

प्रिय साथियो, स्वच्छता केवल सुंदरता का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। यदि हम आज जिम्मेदारी से कार्य करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित मध्यप्रदेश दे पाएंगे। आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें : मेरा कचरा - मेरी जिम्मेदारी। एक बार फिर आप सभी से अपील है कि अपने मध्यप्रदेश को देश में कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में स्वच्छ, सुंदर और संवहनीय (सस्टेनेबल) राज्य बनाने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के सफल क्रियान्वयन में अपना योगदान दें।

जय हिन्द, जय मध्यप्रदेश !

- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी | D-11051/26 | आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2026

आस्था की तिजोरी

सभ्यता का इतिहास बताता है कि किसी समाज की सबसे बड़ी संपत्ति उसका धन नहीं, उसका विश्वास होता है। मंदिरों में चढ़ाया गया दान केवल मुद्रा का लेन-देन नहीं होता; वह श्रद्धालु के विश्वास, त्याग और समर्पण का मौन संकल्प होता है। कोई किसान अपनी फसल का हिस्सा अर्पित करता है, कोई मजदूर अपनी दिनभर की कमाई में से कुछ रुपये निकालता है, तो कोई परिवार अपनी मनोकामना पूरी होने पर सोना-चांदी चढ़ाता है। यह सब ईश्वर को नहीं, उस विश्वास को समर्पित होता है कि यह अमानत धर्म और लोककल्याण की रक्षा करेगी। इसलिए जब इसी अमानत में खयानत की खबरें सामने आती हैं, तो चोट तिजोरी पर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था पर लगती है। अयोध्या और बद्रीनाथ से जुड़े हालिया विवाद इसी पीड़ा को सामने लाते हैं। कहीं दानराशि में अनियमितताओं के आरोप हैं, कहीं मंदिर की संपत्तियों पर अवैध कब्जों की चर्चा है। इन मामलों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएं समाज के भीतर गहरा अविश्वास पैदा करती हैं। मंदिरों की पवित्रता केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना का आधार भी है। सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि आरोप किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों पर लगते हैं जिन्हें मंदिरों की सेवा और संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। जब रक्षक ही संदेह के घेरे में आ जाए, तब प्रश्न केवल अपराध का नहीं, बल्कि नैतिक पतन का बन जाता है। धर्म का प्रभाव उपदेशों से नहीं, बल्कि उसके प्रतिनिधियों के आचरण से तय होता है। देश के बड़े मंदिरों के पास श्रद्धालुओं के दान से अर्जित विशाल संसाधन हैं। यह संपदा किसी व्यक्ति, परिवार या समूह की निजी विरासत नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक धरोहर है। इसलिए उसका प्रत्येक रुपया पारदर्शिता, ईमानदारी और लोककल्याण की कसौटी पर खर्च होता दिखाई देना चाहिए। यदि दानराशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, गौसंरक्षण, संस्कृत अध्ययन, आपदा राहत और निर्धनों की सेवा जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से हो, तो मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण के भी प्रेरक बन सकते हैं। समय की मांग है कि सभी बड़े मंदिरों और ट्रस्टों के लिए नियमित स्वतंत्र ऑडिट, डिजिटल लेखा-जोखा, सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट और जवाबदेही की अनिवार्य व्यवस्था बनाई जाए।

प्रधानमंत्री की इंडो- पैसिफिक यात्रा, एक्ट ईस्ट नीति का व्यापक स्वरूप

किशन सनमुखदास भावनानी
स्तंभकार

वैश्विक स्तरपर भारतीय पीएम की 6 से 11 जुलाई 2026 तक की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की छह दिवसीय यात्रा पर भारत से लेकर पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई हैं। यहकेवल तीन देशों का राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की लगभग एक दशक से अधिक समय से विकसित हो रही एक्ट ईस्ट नीति का सबसे परिपक्व और व्यापक स्वरूप है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हिंद- प्रशांत क्षेत्र विश्व राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था,समुद्री व्यापार, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सामरिक संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, विश्व की लगभग आधी आबादी, वैश्विक जीडीपी का बड़ा हिस्सा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार काअधिकांश भाग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि भारत का इस क्षेत्र में सक्रिय,संतुलित और बहु आयामी नेतृत्व केवल उसकी विदेश नीति का विस्तार नहीं बल्कि उसकी वैश्विक भूमिका का पुनर्परिभाषण भी है। यही कारण है कि इस यात्रा को एक्ट ईस्ट नीति के एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है।यह यात्रा केवल एक नियमित विदेश दौरा नहीं है, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें भारत स्वयं को हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के एक उत्तरदायी, विश्वसनीय और निर्णायक साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है।जिसपर भारत से पूरे विश्व की नजरें लगी हुई है इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति, मुक्त, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक,समुद्री सुरक्षाव्यापार प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों, आपूर्ति श्रृंखला और लोगों के बीच संबंधों को नई गति देना है। इस दौरान तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय वार्ता, व्यापारिक समुदाय से संवाद और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संपर्क कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

साथियों, आज विश्व की भू-राजनीति का केंद्र तेजी से हिंद - प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रहा है। वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा भाग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जबकि ऊर्जा आपूर्ति,डिजिटल कनेक्टिविटी और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क भी इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। ऐसे समय में भारत का उद्देश्य केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है,बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत करना भी है जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून,नौवहन की स्वतंत्रता और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान बना रहे। यही कारण है कि इस यात्रा को अनेक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ 2026 की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलों में से एक मान रहे हैं।भारत की एक्ट ईस्ट नीति अब केवल दक्षिण- पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित नहीं रही। यह आर्थिक, सामरिक, तकनीकी और समुद्री साझेदारी का व्यापक ढांचा बन चुकी है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड इस रणनीति के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। साथियों, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम-बहुल लोकतंत्र है और मलक्का जलडमरूमध्य के निकट उसकी रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत सुरक्षा का प्रमुख भागीदार है, जबकि न्यूज़ीलैंड के साथ व्यापार, कृषि, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएँ हैं।इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक आयाम चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है।भारत ने कहीं भी प्रत्यक्ष टकराव की नीति नहीं अपनाई है,लेकिन वह नियम- आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संतुलित शक्ति संरचना का समर्थन करता है। दक्षिण चीन सागर, समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर भारत समान विचार वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा किसी सैन्य गठबंधन का संदेश नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, संतुलन और साझेदारी का संकेत है।भारत और इंडोनेशिया के संबंध इस यात्रा में विशेष महत्व रखते हैं। दोनों देश हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले समुद्री क्षेत्र में स्थित हैं। रक्षा सहयोग,समुद्री निगरानी, डिजिटल साझेदारी, बंदरगाह विकास और संभावित रक्षा निर्यात जैसे विषय एजेंडे में शामिल हैं। विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइल और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चर्चा अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक समुदाय की निगाहों में है।

साथियों, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति से मजबूत हुए हैं। आज दोनों देश केवल लोकतांत्रिक साझेदार नहीं बल्कि महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी भी हैं।रक्षा अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति इस संबंध के प्रमुख आधार बन चुके हैं।विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण खनिज भारत के ऊर्जा संक्रमण और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।विश्व अर्थव्यवस्था आज आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। महामारी, भू- राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों ने देशों को विश्वसनीय साझेदार खोजने के लिए प्रेरित किया है। भारत इस अवसर को विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलना चाहता है। यदि इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, लॉजिस्टिक्स और महत्वपूर्ण खनिजों पर नए समझौते आगे बढ़ते हैं तो इसका प्रभाव भारतीय उद्योग,रोजगार और निर्यात पर भी सटीकता से दिखाई दे सकता है। साथियों, न्यूज़ीलैंड यात्रा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि कई दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा मानी जा रही है।

अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि भारतीय पीएम की इंडो- पैसिफिक यात्रा को केवल तीन देशों की यात्रा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से वह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन,सहयोग,आर्थिक विकास और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थक बनकर उभरना चाहता है। यदि इस यात्रा से व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और निवेश के क्षेत्रों में ठोस प्रगति होती है, तो इसका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि पूरे इंडो- पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक संरचना पर भी दिखाई देगा। यही कारण है कि विश्व के नीति- निर्माता,रणनीतिक विशेषज्ञ, निवेशक और सामान्य नागरिक इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के रूप में देख रहे हैं।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

वैश्विक पटल पर विविधताओं के साथ चमकती भारत की शिल्प विरासत

ओ.पी. पाल
स्तंभकार

भारत की धरती केवल विविधताओं का देश नहीं बल्कि यह सदियों पुरानी कला, संस्कृति और शिल्प कौशल का जीवंत कोलाज भी है। कश्मीर के पहाड़ों में बुनी जाने वाली पश्मीना शॉल से लेकर दक्षिण के तटीय इलाकों में पहने जाने वाले मुंडू वस्त्रों तक, बनारस की गलियों की हथकरघा मशीनों से लेकर मध्य प्रदेश के चंदेरी सिल्क तक भारत का हर कोना अपनी विशिष्ट कलात्मक पहचान रखता है। लेकिन, इस बदलते युग में आधुनिक, गतिशील और डिजिटल हो रहे बाज़ार में इन पारंपरिक शिल्पों के सामने जगह बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती को अवसर में बदलने और भारत के ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों कारीगरों को आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 'इंडिया हैंडमेड' डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, जो आज भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं के लिए मजबूत 'डिजिटल इंडिया ब्रिज' बन चुका है बल्कि यह वैश्विक स्तर पर देश के आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई पटकथा भी लिख रहा है।

साल 2023 में लॉन्च हुआ यह मंच भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित यह समर्पित ई-कॉमर्स पोर्टल है, जो हमारी पारंपरिक विरासत को संरक्षित कर रहा है। 'इंडिया हैंडमेड' न केवल भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रहा है, बल्कि करीब 65 लाख शिल्पी कारीगरों को व्यापक बाजार देकर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंडिया' के विजन को भी मजबूत कर रहा है।

'इंडिया हैंडमेड' पोर्टल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के नारे को धरातल पर सच करता नजर आ रहा है। यह मंच केवल आर्थिक लेन-देन की जगह नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का भी मजबूत उपकरण है। जब दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा व्यक्ति इस पोर्टल से कोई हस्तनिर्मित वस्तु खरीदता है तो वह केवल उत्पाद नहीं खरीद रहा होता बल्कि वह उस भारतीय कारीगर की उंगलियों के जादू, उसकी पीढ़ियों की विरासत और भारत की मिट्टी की कहानी को अपने घर ले जा रहा होता है। जैसे-जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया हैंडमेड यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारी प्राचीन कलाएं और तकनीकें पीछे न छूट जाएं।

यह मंच आधुनिकतम ई-कॉमर्स तकनीक और प्राचीनतम मानवीय कौशलों का अद्भुत और सफल संगम है। यह हमारे बुनकरों और शिल्पकारों को केवल जीवित रहने का साधन नहीं दे रहा बल्कि उन्हें सम्मान, वैश्विक पहचान और समृद्धि का नया आसमान दे रहा है। इंडिया हैंडमेड के माध्यम से भारत की यह अनमोल विरासत न केवल सुरक्षित है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर आजीविका, नवाचार और गौरव का शाश्वत स्रोत बनकर चमक रही है। प्रत्येक भारतीय और वैश्विक नागरिक के लिए इस मंच से जुड़ना भारत की आत्मा और उसकी कलात्मक धड़कन से जुड़ने जैसा है।

भारत का हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र, कृषि के बाद देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वस्त्र मंत्रालय के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 64.66 लाख हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर हैं। मसलन देश में 71 प्रतिशत हथकरघा बुनकरों में 64 प्रतिशत महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी इस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत और मजबूत सामाजिक संरचना है। यानी जब एक ग्रामीण महिला बुनकर के बनाए उत्पाद को वैश्विक मंच मिलता है तो वह न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है बल्कि अपने पूरे परिवार और समुदाय की सामाजिक स्थिति को भी बदल देती है। यही एक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। यह एक ऐसा ई-कॉमर्स पोर्टल है जो पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' और 'हैंडमेड' (हाथ से बने) उत्पादों के लिए समर्पित है। यहाँ मशीनी या कृत्रिम रूप से तैयार उत्पादों की कोई जगह नहीं है, जिससे हस्तनिर्मित कला की शुद्धता और प्रामाणिकता बनी रहती है। इंडिया हैंडमेड के माध्यम से अब कारीगर सीधे देश-विदेश के खरीदारों से जुड़ते हैं, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित और पारदर्शी मुआवजा मिलता है। एक छोटे से गांव में रहने वाले हुनरमंद शिल्पकार के पास पहले केवल स्थानीय मेलों या हाट-बाजारों तक ही पहुंच होती थी। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके उत्पादों को एक क्लिक पर करोड़ों ग्राहकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उनकी बाजार सीमाएं असीमित हो गई हैं।

इंडिया हैंडमेड की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रोजमर्रा के उत्पादों के साथ-साथ भारत की विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान वाले शिल्पों को एक वीआईपी स्थान देता है। इसके तहत दो प्रमुख सरकारी पहलों को इस मंच पर विशेष रूप से एकीकृत किया गया है, जिसमें जीआई-टैग और ओडीओपी शामिल है। जीआई-टैग किसी उत्पाद की उस विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषताओं को प्रमाणित करता है जो मुख्य रूप से उसके भौगोलिक उद्गम के कारण होती हैं। इंडिया हैंडमेड पर खरीदार देश के कोने-कोने के प्रामाणिक जीआई उत्पादों को खरीद सकते हैं। इनमें उत्तराखंड की ऐपन कला, कश्मीर की सबसे नरम और बेशकीमती शुद्ध पश्मीना शॉल, केरल के पारंपरिक सूती वस्त्रों में शुमार मुंडू उत्पाद, यूपी के वाराणसी रेशमी बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी (सिल्क उत्पाद), गोरखपुर व अन्य क्षेत्र के मिट्टी से बनी जीवंत मूर्तियां और घरेलू सजावट के सामान टेराकोटा उत्पाद, मध्य प्रदेश की चंदेरी सिल्क, पश्चिम बंगाल की बारीक सूती बुनाई और हाथ से तैयार तंगेल साड़ी और झारखंड/बिहार के प्राकृतिक सुनहरे रंग और अनूठे टेक्सचर जैसे उत्पाद भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'एक जिला एक उत्पाद' का हिस्सा बन चुके हैं।

'दस्तकार क्राफ्ट' इस मंच के जरिए 500 से अधिक स्थानीय कारीगरों के हुनर को सीधे वैश्विक बाजार में ले आया है। इसके अलावा विलेज क्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे कुशल कारीगरों द्वारा बेहद प्यार और सावधानी से बनाए गए सूती तौलिए, पारंपरिक गमछे और आरामदायक बेडशीट इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी विरासत केवल खास मौकों पर सजाने के लिए नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को आराम और गुणवत्ता देने के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अपडेट

डिप्रेशन और नींद की समस्या के लिए कारगर हो रहा 'लाइट थेरेपी' का उपयोग

डिप्रेशन और नींद की समस्याएं आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही हैं। खराब नींद, लगातार थकान, चिड़चिड़ापन और उदासी न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में हाल के वर्षों में 'लाइट थेरेपी' एक ऐसी तकनीक के रूप में चर्चा में आई है जो मूड में सुधार करने और नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कई स्टडी में इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया गया है। यह प्रभाव खासकर उन लोगों में देखने को मिलते हैं, जो मौसमी अवसाद या सर्केडियन रिद्म से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

लाइट थेरेपी एक ऐसा मॉर्डन ट्रीटमेंट है जिसमें व्यक्ति विशेष प्रकार के कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में नियंत्रित समय तक बैठता है। इसके लिए आमतौर पर एक विशेष लाइट थेरेपी बॉक्स का उपयोग किया जाता है जो नेचुरल डे लाइट की नकल करता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार, लाइट थेरेपी विशेष रूप से सिजनल एफेटिव डिसऑर्डर में उपयोगी पाई गई है, जो मौसम में बदलाव के दौरान होने वाला एक प्रकार का डिप्रेशन है। इस थेरेपी का उद्देश्य शरीर की जैविक घड़ी को प्रभावित करना होता है। यह वही आंतरिक प्रणाली है जो हमारे सोने-जागने के चक्र, हार्मोन उत्पादन और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करती है।

हमारा शरीर प्रकाश के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। सुबह की रोशनी ब्रेन को सिग्नल देती है कि जागने और सक्रिय होने का समय है। यह प्रक्रिया मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोनों को प्रभावित करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार, प्रकाश का संपर्क शरीर की आंतरिक घड़ी को रीसेट करने और नींद-जागरण चक्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मेलाटोनिन नींद को नियंत्रित करता है, जबकि सेरोटोनिन मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। पर्याप्त प्रकाश न मिलने पर इन हार्मोनों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे नींद की गुणवत्ता और अधिकांश विशेषज्ञ सुबह के समय इसका उपयोग करने की सलाह देते हैं। प्रकाश की दिशा में बैठना पर्याप्त होता है, सीधे लगातार घूरना जरूरी नहीं है। शुरुआत में कम समय के लिए थेरेपी लें और जरूरत के अनुसार अवधि बढ़ाएं। हालांकि यह हर व्यक्ति के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं होती और इसे चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। सही उपकरण, सही समय और विशेषज्ञ की सलाह के साथ उपयोग करने पर लाइट थेरेपी मानसिक और नींद संबंधी स्वास्थ्य सुधारने का एक उपयोगी सहायक साधन बन सकती है।

सुविचार

क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा।
कुछ ना होगा तो तर्जुबा होगा।
– अज्ञात

निशाना

आदमी के लिए मत लड़ो..!

रामकिशोर नाविक

आदमी के लिये मत लड़ो
फ्रेम में आदमीयत जड़ो
इस ज़माने का दस्तूर है
पेट पर पाँव रखकर बढ़ो
खूब दंगे कराओ स्वयं
दाड़ी टोपी के सर पर मढ़ो
रात दिन कागज़ों को रंगो
ये ज़रूरी नहीं कुछ पढ़ो
तिकड़मों के कलाकार बन
उन्नति के शिखर पर चढ़ो

टेक्नो अपडेट

AC को रिप्लेस कर सकती है हीट पंप तकनीक, आधी बिजली में हीट और कूलिंग

जहां गर्मियों में ठंडक के नाम पर हमें सिर्फ ऐसी याद आता है वहीं एक तकनीक ऐसी भी है, जो ऐसी से आधी बिजली खपत में ठंडक और गर्मी दोनो दे सकती है। यह रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करती है, जो गर्मी या ठंडक पैदा नहीं करती बल्कि गर्मी को एक जगह से सोखकर दूसरी जगह पर पहुंचाती है और सर्दियों में ऐसा ठंडक के साथ कर सकती है। अब यह विंडो एसी के आकार में भी उपलब्ध है, जिसे विंडो हीट पंप कहा जाता है।

गर्मियों में 45-50 डिग्री की तपती भीषण गर्मी और सर्दियों में हाड़ कंपाने वाली ठंड, ये मौसम के वो दो रूप हैं, जिन्हें सभी उत्तर भारतीय हर साल झेलते हैं। इन दोनों ही मौसम में एसी और हीटर का लोड बिजली के मीटर को रॉकेट की रफ्तार से भगाता है, जिससे बिजली बिल काफी आता है। अब सोचिए एक ऐसी अकेली मशीन के बारे में जो हर मौसम की तकलीफ को दूर कर दे और एसी या हीटर जितनी बिजली भी ना खाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं विंडो AC की तरह दिखने वाले विंडो हीट पंप तकनीक की। इसकी खासियत है कि यह गर्मियों में कमरे को ठंडा और सर्दियों में कमरे को गर्म कर सकती है। इतना ही नहीं यह काम एसी या हीटर के मुकाबले आधे दाम में हो सकता है।

विंडो हीट पंप तकनीक क्या है?: विंडो AC की तरह दिखने वाली यह तकनीक कूलिंग और हीटिंग दोनों का काम कर सकती है। हालांकि इसके काम करने का तरीका और फीचर्स काफी अलग होते हैं। विंडो हीट पंप रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल तकनीक पर काम करते हैं। इसकी वजह से यह गर्मियों में कमरे की गर्मी को सोखकर बाहर निकाल देते हैं। यह कुछ-कुछ वैसा ही है, जैसे कि एक AC काम करता है। वहीं सर्दियों में यह बाहर के वातावरण से गर्मी को खींचकर कमरे में ट्रांसफर कर देता है। कहने का मतलब है यह तकनीक बिजली से गर्मी या ठंडक पैदा नहीं करती बल्कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देती है। विंडो हीट पंप किसी भी आप AC या हीटर के मुकाबले बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है। इसकी वजह है कि विंडो हीट पंप को बिजली का इस्तेमाल करते हुए ठंडक या गर्मी पैदा नहीं करनी पड़ती। सेंट्रलाइज्ड हीटिंग/कूलिंग सिस्टम की तरह यह घर के साथ परमानेंट तौर पर अटैच नहीं होता। इसे जब चाहे निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया जा सकता है। किराए पर रहने वालों के लिए यह एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

अजब - गजब

ये हैं चोरों के यमराज! भैंस पर बैठकर पेट्रोलिंग और चोर पकड़ती है पुलिस

ये हैं असली बफेलो सोल्जर्स! ब्राजील के उत्तरी इलाके में स्थित मराजो आइलैंड पर पुलिस की पेट्रोलिंग का तरीका पूरी दुनिया के लिए अनोखा और रोमांचक है। यहां के करीब 200 पुलिस अधिकारी घोड़ों, जीपों या कारों की जगह भैंसों पर सवार होकर सड़कों और दलदलों में गश्त लगाते हैं। चोरों और अपराधियों के लिए ये पुलिस वाले सचमुच यमराज बन चुके हैं।

मराजो आइलैंड ब्राजील का सबसे बड़ा द्वीप है, जो स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है। यहां आधे साल तक भारी बारिश और बाढ़ आती है। पूरा इलाका मैंग्रोव दलदल में तब्दील हो जाता है। ऐसी स्थिति में ना तो सड़कों पर कार चल पाती है, ना बाइक और कई बार नाव भी फंस जाती है। ऐसे में पुलिस ने स्थानीय भैंसों को अपना सबसे भरोसेमंद वाहन बना लिया। ये भैंस दलदल, पानी और कीचड़ में आसानी से चल सकती हैं और ऊंचाई के कारण पुलिसकर्मियों को बेहतर नजर भी आती है।

ये भैंसें ना सिर्फ परिवहन का साधन हैं बल्कि अपराधियों को पकड़ने में भी बेहद कारगर साबित हो रही हैं। भैंस पर सवार पुलिस वाले अचानक हमला कर अपराधियों को दबोच लेते हैं। स्थानीय लोग इन्हें 'बफेलो सोल्जर्स' कहकर पुकारते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस अनोखे तरीके से अपराध दर में काफी कमी आई है। चोर और तस्कर अब इन इलाकों में घुसने से पहले सोचते हैं क्योंकि भैंस सवार पुलिस कहीं भी पहुंच सकती है। मराजो आइलैंड पर रहने वाले लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने, कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहां अवैध लॉगिंग, मादक पदार्थों की तस्करी और छोटे-मोटे अपराध आम हैं। सामान्य वाहनों के अभाव में पुलिस को पहले काफी परेशान रहती थी। लेकिन जब उन्होंने भैंसों का इस्तेमाल शुरू किया तो स्थिति बदल गई है। भैंसें सस्ती, रखरखाव में आसान और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं।

आम है नजाराः एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भैंस पर बैठकर पेट्रोलिंग करना अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। सुबह से शाम तक वे भैंसों पर सवार होकर गांव-गांव, जंगलों और दलदली इलाकों में घूमते हैं। वे ना सिर्फ अपराध रोकते हैं बल्कि लोगों की मदद भी करते हैं। बाढ़ के समय में ये भैंसें लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में भी उपयोगी साबित होती हैं।

न्यूज विंडो

पुलिस की बड़ी सफलता

हत्या के मामले में पैरोल से फरार सजायाफ्ता आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

तेंदूखेड़ा। पुलिस ने हत्या के प्रकरण में कारावास की सजा प्राप्त कर पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना तेजगढ़ क्षेत्र के हत्या के एक प्रकरण में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दंडित आरोपी दशरथ अहिरवार पिता धनुआ अहिरवार, उम्र 41 वर्ष, निवासी झलौन को वर्ष 2019 में पैरोल पर रिहा किया गया था। पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी वापस जेल नहीं लौटा और लगातार फरार चल रहा था। आरोपी की अनुपस्थिति के कारण माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा उसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था

पुलिस अधीक्षक दमोह आनंद कलादगी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास किए गए अनुविभागीय अधिकारी तेंदूखेड़ा अर्चना अहीर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से लगातार तलाश की गई। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप पुलिस टीम ने आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले के अंबी गांव में चिन्हित की। योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वहां दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधिवत दमोह लाया गया तथा न्यायालय, दमोह के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे पुनः जेल भेज दिया गया।पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से वर्षों से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया है। यह कार्रवाई फरार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान की सफलता का महत्वपूर्ण उदाहरण है तथा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अमरकंटक नपं की नई बाजार बैठकी वसूली का व्यापारियों ने किया विरोध

अनुपपुर। नगर परिषद अमरकंटक द्वारा जारी सूचना के अनुसार 1 जुलाई 2026 से नगर क्षेत्र में दैनिक एवं साप्ताहिक बाजार बैठकी शुल्क की नई दरें लागू कर दी गई हैं। परिषद ने दैनिक बाजार बैठकी 30 रुपये प्रतिदिन तथा साप्ताहिक बाजार में छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों के लिए क्रमशः 20, 50 और 70 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। नई व्यवस्था लागू होते ही स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही व्यापार मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में अतिरिक्त शुल्क का बोझ छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा। कई व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शुल्क निर्धारण से पहले व्यापारिक संगठनों और प्रभावित लोगों से कोई व्यापक चर्चा नहीं की गई। व्यापारियों का कहना है कि यदि नगर परिषद बाजार क्षेत्र में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार करती है तो शुल्क वसूली उचित मानी जा सकती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्थाओं को देखते हुए बढ़ी हुई वसूली उचित नहीं लगती।

वहीं नगर परिषद का कहना है कि परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर यह निर्णय लिया गया है और इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग नगर की सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। व्यापारियों ने परिषद से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

हाई कोर्ट ने दी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत, मानदेय में की गई कटौती को अस्वीकार्य माना

जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में की गई कटौती को अस्वीकार्य माना है।हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने अंशदान में वृद्धि किए जाने का लाभ कर्मियों तक पहुंचना चाहिए था, न कि राज्य सरकार अपने हिस्से में कटौती कर उनका वास्तविक मानदेय कम कर दे।हालांकि कोर्ट ने एकलपीठ के उस आदेश में संशोधन किया है, जिसमें बकाया राशि पर ब्याज देने के निर्देश दिए गए थे। अब कार्यकर्ताओं को एरियर तो मिलेगा, लेकिन उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। कर्ट ने राज्य शासन की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा।यह मामला मप्र बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन, भोपाल की याचिका से जुड़ा है। याचिका में कहा गया था कि 27 जून, 2019 के बाद केंद्र सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से में कटौती कर दी।

विधायक उमाकांत शर्मा के विधानसभा प्रश्न का बड़ा असर

213 शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त किया, मूल विद्यालयों में लौटना पड़ेगा

सिरोंज, दोपहर मेट्रो

लगभग एक वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश विधानसभा में सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न का बड़ा असर सामने आया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति (अटैचमेंट) पर कार्यरत 213 शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त करते हुए उन्हें उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजने के आदेश जारी किए हैं। इस निर्णय से प्रदेश के अनेक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है तथा विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन का लाभ मिलेगा।

गौरतलब है कि विधायक उमाकांत शर्मा ने 30 जुलाई 2025 को विधानसभा में प्रश्न लगाकर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यालयों में अटैच शिक्षकों की जानकारी मांगी थी। प्रश्न के माध्यम से उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि बड़ी संख्या में शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में

पढ़ाने के बजाय विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं, जिससे सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

विधानसभा में उठाए गए इस प्रश्न के बाद शासन स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 213 शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इन शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें उनके मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा, 'मैंने 30 जुलाई 2025 को विधानसभा में प्रश्न पूछकर दूसरे कार्यालयों में अटैच शिक्षकों की जानकारी मांगी थी। लगभग एक वर्ष बाद मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान देते हुए 213 शिक्षकों के अटैचमेंट खत्म करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अधिकारियों ने आदेश देने में एक साल की देरी की, फिर भी मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छात्र हित में शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म किया।'

उन्होंने आगे कहा, 'अब भी कई शिक्षक अटैच हैं। उनका अटैचमेंट भी समाप्त किया जाए, क्योंकि स्कूल शिक्षक विहीन हैं। इसलिए शिक्षकों के अपने मूल विभाग में काम करने पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि बाद में फिर अटैचमेंट न हो।'

विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन शेष अटैच शिक्षकों को भी शीघ्र उनके मूल विद्यालयों में भेजेगा, जिससे प्रदेश के सभी विद्यालयों में सुचारु रूप से शिक्षण कार्य संचालित हो सकेगा।

यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है तथा विधानसभा में उठाए गए जनहित के प्रश्न की बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है।

प्रेम विवाह के 10 साल बाद खूनी अंत, शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम

चरित्र शंका में पत्नी की गला दबाकर हत्या, शव बिस्तर की पेटी में छिपाकर ऊपर सोता रहा पति

वारदात के समय बुआ के घर गए थे चारों बच्चे, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

धार, दोपहर मेट्रो

जिले की सरदारपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम राजगढ़ नगर के भानगढ़ रोड स्थित शंकरपुरा क्षेत्र में चरित्र शंका के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी, हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर में रखी बिस्तर पेटी के अंदर छिपा दिया और रातभर उसी पेटी के ऊपर सोता रहा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है।

सुबह खुला राज, पेटी से मिला शव

राजगढ़ थाना पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह शंकरपुरा क्षेत्र से हीना खराड़ी के लापता होने की सूचना मिली थी। परिजनों ने हीना के पति कमलेश खराड़ी के व्यवहार पर संदेह जताया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमलेश से पूछताछ की। जवाबों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने घर की तलाशी ली। इस दौरान जब बिस्तर पेटी को खोला गया, तो उसके अंदर से हीना का शव बरामद हुआ।

शराब के नशे में हुआ था विवाद

प्रारंभिक जांच और पुलिस पूछताछ में आरोपी कमलेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि वह पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। सोमवार रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद शराब के नशे में धुत्त कमलेश ने हीना का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कमलेश और हीना ने करीब 10 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। लेकिन पिछले कुछ समय से कमलेश को शराब की लत लग गई थी, जिससे घर में रोज विवाद होता था। सोमवार रात को भी जब पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ, तो डर के मारे दंपति के चारों बच्चे तीन बेटियां और एक बेटा) रात में ही अपनी बुआ के घर सोने चले गए थे। बच्चे जब सुबह लौटे, तब इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ।

आरोपी पति कमलेश को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच जारी है

- समीर पाटीदार, थाना प्रभारी राजगढ़

महिला सुरक्षा को नई मजबूती : धार में बनेगा 1.43 करोड़ का अत्याधुनिक महिला थाना

धार। जिले में महिला सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा धार में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए महिला थाना भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। भवन निर्माण के लिए निगम ने ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं।

वर्तमान में महिला थाना कंट्रोल रूम के समीप संचालित हो रहा है, जहां जिले के दूर-दराज़ क्षेत्रों से आने वाली महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचती हैं। नए भवन के निर्माण से महिलाओं को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक वातावरण मिलेगा, वहीं महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध होगा। नए महिला थाना भवन के निर्माण की समय-सीमा 10 माह निर्धारित की गई है। भवन में आधुनिक पुलिसिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे महिला संबंधी अपराधों की सुनवाई और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी।

एक से अधिक ऑनलाइन चालान वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन व चालक लाइसेंस होंगे निरस्त

नागरिक अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन अवश्य करें: कलेक्टर

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्मार्ट सिटी के परियोजना कार्यों की समीक्षा की

सागर, दोपहर मेट्रो

ऐसे सभी वाहन चालकों की सूची तैयार करें जिनके एक से अधिक ऑनलाइन चालान है और आरटीओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस निरस्त कराने की कार्यवाही करें, उक्त निर्देश कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्टरेट कार्यालय में स्मार्ट सिटी के परियोजना कार्यों की समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का प्रजेंटेशन देखा और बिंदुवार समीक्षा की। शहर के यातायात की स्मार्ट सिटी के इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही ऑनलाइन निगरानी और चालानी कार्यवाही की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा की सड़क

सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पालन करना व कराना अनिवार्य है। उन्होंने अपील करते हुए कहा की नागरिक अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा हेतु वाहन का उपयोग करते समय यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। जैसे की दोपहिया वाहन पर वाहन चालक व पीछे बैठने वाला दोनों ही हेलमेट लगायें, तीन सवारी न बैठाएं, चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। उन्होंने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा की ऐसे वाहनचालक जो बार बार नियमों का उल्लंघ करते हैं उनकी अलग से लिस्ट बनाएं और उनके वाहन पुलिस की मदद से जब्त करायें।

उन्होंने कहा की स्मार्ट सिटी के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है इनका कुशल संचालन नागरिकों की सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा। हमारी प्राथमिकता है की सागर के रहवसियों को बेहतर से बेहतर तकनीकी उपलब्ध हो और अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उन्हें मिले। उन्होंने कहा की आईसीसीसी को आज की पीढ़ी के अनुरूप और विकसित करें एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का भी प्रयोग करें।

पिछले दिनों की घटनाओं में अलग-अलग बाघ शामिल

रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो बाघ सक्रिय

सागर. वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व दो बाघ सक्रिय हैं. यह खुलासा वन विभाग ने किया है. बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2025 के दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स से दोनों बाघ अलग-अलग होने की पुष्टि हुई है. गौरतलब है कि वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के मोहली परिक्षेत्र में गत 5 जुलाई को गश्त के दौरान दो वनकर्मियों के निकट आने पर एक बाघ द्वारा उन पर हमला कर दिया गया था। इस घटना में श्रमिक बाबूलाल रैकवार के पैर में गहरी चोट आई थी।

घटना के बाद बाघ की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास हाथियों से सघन गश्त की गई। 7 जुलाई को प्रातः गश्त के दौरान महावत को घटनास्थल के समीप एक बाघ शावक दिखाई दिया। नवंबर 2025 में कैमरा ट्रैपिंग में भी इस बाघ शावक की तस्वीर आई थी, तब उसकी आयु 9 से 12 माह अनुमानित की गई थी। वर्तमान में इसकी आयु लगभग 15 से 18 माह है।

वनकर्मियों के बयान और पंजों के आकार के आधार पर संभावना है कि यह वही शावक है जिसने वनकर्मी को घायल किया था। कुछ दिन पहले पटना मोहली गांव में भी एक बाघ द्वारा ग्रामीण को घायल किए जाने की घटना हुई थी।

कुछ लोगों द्वारा भ्रामक रूप से दोनों घटनाओं में एक ही बाघ होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अखिल भारतीय बाघ गणना 2025 के दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स से दोनों बाघ अलग-अलग होने की पुष्टि हुई है।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिजर्व क्षेत्र में दो अलग-अलग बाघ सक्रिय हैं और वन्यजीव सुरक्षा तथा स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को लेकर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

मेट्रो एंकर

दवा के इस्तेमाल के बाद बीज का नहीं हुआ अंकुरण

फसल खराब होने से परेशान किसान ने कीटनाशक पीकर किया आत्महत्या का प्रयास, हालत गंभीर

धार, दोपहर मेट्रो

बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगरा में सोयाबीन की फसल अंकुरित न होने से परेशान एक किसान ने खाद-बीज दुकान पर कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग और परिजन उसे गंभीर हालत में तुरंत समीप के अस्पताल ले गए, जहां से उसे एक निजी अस्पताल में रैफर किया गया है। फिलहाल किसान का उपचार जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर निगरानी रख रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम दत्तीगरा निवासी किसान प्रहलाद सिंह राठौर और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी करीब साढ़े दस बीघा कृषि भूमि पर बीती 27 जून को सोयाबीन की बोवनी की थी। परिजनों ने बताया कि बोवनी के दौरान उन्होंने 'वरदान' नामक दवा की दो बोतलों का उपयोग किया था, जिसकी कीमत करीब 700 रुपये प्रति बोतल थी। किसानों का आरोप है कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद लगभग 10 बीघा क्षेत्र में सोयाबीन का एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, जिससे पूरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान के परिजनों ने एक महत्वपूर्ण बात साझा करते हुए बताया

कि उन्होंने अपनी करीब ढाई बीघा भूमि में इस दवा का उपयोग नहीं किया था। उस हिस्से में सोयाबीन की फसल सामान्य रूप से अंकुरित हुई है। इस अंतर को देखते हुए किसानों को पूरा अंदेशा है कि फसल खराब होने का मुख्य कारण वह दवा ही है। फसल न उगने से किसान को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान था।

संतोषजनक जवाब न मिलने पर उठाया कदम

इसी समस्या और आर्थिक नुकसान की शिकायत लेकर पीड़ित किसान संबंधित खाद-बीज विक्रेता की दुकान पर पहुंचा था। उसने दुकानदार को फसल खराब होने की पूरी बात बताई और अपनी परेशानी रखी। परिजनों का आरोप है कि जब दुकानदार की ओर से उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उसकी समस्या को अनसुना कर दिया गया, तो हताश होकर किसान ने दुकान में ही रखी कीटनाशक दवा पी ली। किसान द्वारा अचानक उठाए गए इस कदम से दुकान और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए उसे बाइक पर बैठाया और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और संबंधित विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है, और मामले की जांच की जा रही है।

कार्यालय थाना प्रभारी थाना निशातपुरा नगरीय पुलिस भोपाल

क्र.था.प्र./488/गुम. क्र. 89/26 दिनांक 03/07/26

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि थाना निशातपुरा जिला भोपाल (म.प्र.) के गुम. क्रमांक 89/26 में सूचनाकर्ता सेवेन्द्र विश्वकर्मा पिता रामगोपाल विश्वकर्मा उम्र 26 साल निवासी ग्राम सुनेटी तहसील बेगमगंज जिला रायसेन मो.न. 7724996501 की सूचना पर गुमशुदा आजाद विश्वकर्मा उम्र 28 साल नि. त्रिवेणी हाइट्स बी ब्लॉक 4th फ्लोर करोंद भोपाल का हुलियाः कद 5.5 फिट, रंग गोरा, बांये हाथ में महाकाल, दाहिने हाथ में मंत्र लिखे है। बदन सिल्वर रंग की शर्ट, ब्लू कलर का पेंट पहने है। उपरोक्त गुमशुदा के बारे कोई जानकारी प्राप्त हो तो थाना निशातपुरा भोपाल मे संपर्क करें तथा थाना मोबाईल नंबर 7587601924, 7987214769 पर तत्काल संपर्क करें।

थाना प्रभारी
थाना निशातपुरा भोपाल

जी-15356/26

सागर को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना प्राथमिकता: लोधी

नवनिर्मित बोट क्लब का हुआ लोकार्पण

सागर। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास विभाग द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक बोट क्लब का लोकार्पण समारोह संजय ड्राइव स्थित लाखा बंजारा झील परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने की।

विशिष्ट अतिथियों के रूप में महापौर संगीता तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी एवं नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार उपस्थित रहे।

नवनिर्मित बोट क्लब का फीता काटकर लोकार्पण हुआ. इस अवसर पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि सागर को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने विधायक शैलेंद्र जैन की मांग पर तालाब से लगी नहर के सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए 5 करोड़ रुपये तथा बोट क्लब में आधुनिक जिम उपकरणों की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण धरोहर है और इसके समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अगले 15 दिनों में यहां फ्लोटिंग जेट्टी भी स्थापित कर दी जाएगी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई पर्यटन नीति लागू कर निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। उनका प्रयास है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने यह भी बताया कि सागर में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एमपीटी) का एक बड़ा होटल स्थापित करने के लिए अधिकारियों को उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

सागर का तालाब शहर की पहचान और धरोहर: शैलेंद्र जैन

विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने कहा कि सागर का तालाब शहर की पहचान और धरोहर है। इसके संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जैन ने बताया कि शहर में जल क्रीड़ा गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 42 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 5 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम के लिए हुआ है। इनमें से 3 बालिकाओं ने विशाखापट्टनम में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर सागर का नाम रोशन किया है.महापौर संगीता तिवारी ने कहा कि जल पर्यटन के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा झील की सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम को श्याम तिवारी ,नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मेघा दुबे, शैलेश केसरवानी,अमित बैसाखिया सहित अनेक नागरिक शामिल थे।

न्यूज विंडो

स्कूली वाहनों पर प्रशासन सख्त एलपीजी से चल रही ईको वैन जब्त

सागर। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया। प्रतिभा पाल के निर्देश पर बंडा और बरायठा क्षेत्र में 18 स्कूली वाहनों की जांच की गई। इस दौरान एक ईको वाहन क्रमांक एमपी-52-बी-0529 एलपीजी गैस किट से संचालित पाया गया। जांच में वाहन में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं मिला और निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हुए पाए गए, जिसके चलते वाहन को जब्त कर लिया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कुछ वाहन चालक रास्ता बदलकर बचने का प्रयास करते दिखे, लेकिन जांच दल ने उन्हें भी जांच के दायरे में लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

रातापानी बफर जोन में 680 पेड़ों की अनुमति लेकर काट दिए हजारों पेड़

रायसेन/मंडीदीप। रायसेन जिले की ग्राम पंचायत समनापुर कला में कथित रूप से हजारों हरे-भरे पेड़ों की कटाई का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का विषय बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि इसे आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों के अनुसार पंचायत ने सुनील मालवीय को 680 पेड़ काटने की अनुमति दी थी। वहीं, समीप स्थित भूमि स्वामी अशोक वासवानी को पंचायत द्वारा कोई अनुमति जारी नहीं की गई। इसके बावजूद दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होने के आरोप लगे हैं। पंचायत सचिव का कहना है कि अनुमति संबंधित अधिकारियों के निर्देश पर दी गई थी। वहीं, राजस्व विभाग इस पूरे मामले की जिम्मेदारी पंचायत पर डाल रहा है। आरोप है कि कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और वन विभाग को जानकारी होने के बावजूद बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होती रही। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने फोटो बताते हैं कि क्षेत्र पहले घने जंगल से आच्छादित था। सूत्रों का दावा है कि रातापानी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 5 हजार से अधिक सागौन सहित अन्य इमारती पेड़ों की कटाई की गई। हालांकि वन विभाग का कहना है कि लकड़ी परिवहन के लिए कोई ट्रांजिट परमिट (टीपी) जारी नहीं किया गया।

नि:शुल्क नेत्र शिविर में 230 मरीजों की हुई जांच; 51 को ऑपरेशन के लिए भेजा

गंजबासौदा। स्थानीय मिल रोड स्थित सदुरु विज़न सेंटर में स्वर्गीय श्री नारायण सदाशिव पिंगले सेवा संस्थान के सहयोग से नि:शुल्क नेत्र परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्वर्गीय तनुज एलिया की स्मृति में उनके जन्मदिन पर 'सेवा दिवस' के रूप में आयोजित किया गया। शिविर में डॉ. सौरभ शर्मा एवं डॉ. राजकरण वर्मा ने 230 से अधिक मरीजों की नेत्र जांच कर उन्हें आंखों की देखभाल एवं नेत्र रोगों से बचाव संबंधी आवश्यक सलाह दी। जांच के दौरान 51 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए, जिन्हें नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए आनंदपुर रेफर किया गया। कैंप प्रभारी जीतू पाठक के निर्देशन में काउंसलिंग टीम ने 39 जरूरतमंद मरीजों को नि:शुल्क चश्मों का वितरण किया, जबकि 109 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई गई। धर्मेंद्र अहिरवार एवं राजकुमार कुर्मी ने 33 मरीजों के चश्मों का नंबर निकाला तथा देवेंद्र जोगी ने मरीजों की ब्लड प्रेशर एवं शुगर की जांच की। शिविर सहयोगी सुनील बाबू पिंगले ने बताया कि ट्रस्ट के रवि उपाध्याय के मार्गदर्शन एवं सदुरु स्वर्गीय श्री रणछोड़दास महाराज की प्रेरणा से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से नि:शुल्क नेत्र शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में समाजसेवी एवं मानव अधिकार सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. ए.के. जैन, वरिष्ठ समाजसेवी गणेशराम रघुवंशी, ऋतुज एलिया, विनोद राठौर, सदुरुदेव अस्पताल के डॉ. धर्मेंद्र अहिरवार, विजय अरोरा, हेमंत भंडारी, पत्रकार संजीव शर्मा, अंकित, मोहन सैनी, साहूजी सहित अनेक समाजसेवी उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि 'नेत्रों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कार्यक्रम में सरदार सिंह सिसोदिया ने विशेष सहयोग दिया। अंत में सुनील बाबू पिंगले ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे नि:शुल्क नेत्र शिविर लगातार आयोजित किए जाएंगे।

कलेक्टर की जनसुनवाई में आईं 152 शिकायतें

खसरा की शिकायतों का 7 दिन में निपटारा करने के निर्देश

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिलेभर से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, सीमांकन, अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी और स्वच्छता समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 152 शिकायतें प्राप्त हुईं। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

जनसुनवाई के दौरान सोहागपुर निवासी जीजन बाई की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम को सीमांकन कर कार्रवाई करने तथा एक सप्ताह में प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए। बनखेड़ी के पीपरपानी निवासी सुशील कुमार शुक्ला की शासकीय भवन के जर्जर होने और उस पर अतिक्रमण की शिकायत पर भवन का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार ध्वस्तीकरण तथा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। माखननगर निवासी पवन यादव के तीन माह से लंबित खसरा अनुमोदन प्रकरण को सात दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं पिपरिया निवासी मीना बाई की प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त नहीं मिलने की शिकायत पर जांच कर पात्रता अनुसार लाभ दिलाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर राजेश शुक्ला, एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण का आश्वासन दिया।

दिव्यांग आवेदकों के बीच पहुंचे कलेक्टर

जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा स्वयं भूतल स्थित कक्ष में पहुंचकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं। माखननगर निवासी लखनलाल के पुत्र को सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश दिलाने, नर्मदापुरम निवासी मोहम्मद शाहरुख को योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने तथा दिव्यांग आवेदिका मनीषा अहिरवार को उपचार एवं पेंशन का लाभ दिलाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही मनीषा अहिरवार को शासकीय वाहन से उनके निवास तक पहुंचाने की व्यवस्था भी कराई गई।

गंजबासौदा : जन चौपाल में गूंजीं वार्डवासियों की कई समस्याएं

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

बारिश में भी कांग्रेस का मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान लगातार जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने बारिश की परवाह किए बिना विभिन्न स्थानों पर जन चौपाल लगाकर वार्डवासियों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। अभियान के दौरान यह संदेश भी दिया गया कि जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस का संघर्ष मौसम की बाधाओं से रुकने वाला नहीं है।

युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अपूर्व जैन ने बताया कि जन चौपाल के दौरान सामने आया कि शहर के कई परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। नागरिकों ने बिजली व्यवस्था सहित अन्य जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया। अभियान के तहत प्राप्त शिकायतों और समस्याओं की सूची तैयार की जा रही है। कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराने का प्रयास किया गया, जबकि शेष समस्याओं का ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की जाएगी। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि पहले संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं के समाधान का प्रयास होगा, लेकिन यदि प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई तो कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रवि तिवारी, पार्षद सौदान सिंह यादव, सुनील बाबू पिंगले, बी.डी. शर्मा, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष जगदीश व्यास आदि मौजूद थे।

सीहोर में फसलों को बचाने मवेशियों को उफनती नदी में हांक रहे किसान

अमरकंटक। दोपहर मेट्रो

जिले के भैरूंदा क्षेत्र के छीपानेर गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग गोवंश को उफनती नर्मदा नदी के गहरे पानी की ओर हांकते और धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि यह कदम कथित तौर पर किसानों द्वारा अपनी फसलों को आवारा गोवंश से बचाने के लिए उठाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, बारिश के मौसम में पशुओं को खुले में छोड़ दिया जाता है। वे नदी किनारे पानी पीने और चरने पहुंच जाते हैं, जहां फसलों की सुरक्षा के लिए कुछ किसान उन्हें नदी की ओर हांक देते हैं। ग्रामीणों का दावा है कि यह प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है और अधिकांश पशु बारिश समाप्त होने के बाद वापस लौट आते हैं, वहीं वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कई लोगों ने इसे पशु क्रूरता बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी घटना पर आपत्ति जताते हुए इसे आस्था से जुड़ा विषय बताया है।

बिना ट्रस्ट बैठक के लाखों रुपए के कार्य स्वीकृत नर्मदा उद्गम ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

अमरकंटक। दोपहर मेट्रो

नर्मदा उद्गम ट्रस्ट की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार ट्रस्ट की पिछले लगभग 2 वर्षों से नियमित बैठक आयोजित नहीं हुई है। ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है कि जब ट्रस्ट की बैठक ही नहीं हुई, तो लाखों रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति किस प्रक्रिया के तहत दी गई और उनका क्रियान्वयन कैसे शुरू कर दिया गया?

जिस संरचना का निर्माण क्षेत्र में मवेशियों, विशेषकर गायों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से किया गया था, वह अपने उद्देश्य को पूरा करती दिखाई नहीं दे रही है। वर्तमान स्थिति में गायें आसानी से उस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। वहीं बारिश के दौरान बाहरी कचरा और मलबा भी उसी मार्ग से अंदर आकर जमा हो रहा है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

बताया जा रहा है कि इस कार्य को स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों से भी जोड़ा गया था, लेकिन मौके की स्थिति देखने पर योजना का अपेक्षित लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता, योजना की उपयोगिता और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नर्मदा उद्गम ट्रस्ट की बैठकों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए, यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किस बैठक या किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई, तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

मेट्रो एंकर धनपुरी स्टॉप डैम मामले में जिम्मेदारों पर चुप्पी, आदित्य हॉस्पिटल के नियम विरुद्ध निर्माण पर भी प्रशासनिक कार्रवाई ठंडी

बहा स्टॉप डैम, बेसमेंट में कारोबार और कार्रवाई अब भी अधूरी

शहडोल। दोपहर मेट्रो

जिले में दो अलग-अलग मामलों ने प्रशासनिक जवाबदेही और कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले वर्ष धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में बना स्टॉप डैम पहली ही बारिश में बह गया था। निर्माण गुणवत्ता और तकनीकी लापरवाही को लेकर सवाल उठे, लेकिन अब तक जांच पूरी होने या जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। संबंधित इंजीनियर आज भी अन्य नगर निकायों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। दूसरी ओर, आदित्य सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विपरीत होने के बावजूद कार्रवाई अधूरी है। नगर पालिका ने वर्ष 2025 में नोटिस जारी कर गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मामला कागजों तक सीमित रह गया। अब एक बार फिर प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोनों मामलों ने जिले में प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही की प्रभावशीलता पर बहस छेड़ दी है। वहीं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत ठाकुर ने कहा कि पुन : नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। इधर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष धनंजय जायसवाल ने कहा कि 'आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है। कार्रवाई की जा रही है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

बेसमेंट में चल रही गतिविधियों पर पहले भी लगा था सवाल

नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत भवन मानचित्र के विपरीत किया जा रहा है। नियमों के अनुसार बेसमेंट का उपयोग पार्किंग, स्टोर या तकनीकी सेवाओं तक सीमित होना चाहिए। इसके बावजूद वहां व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं। नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से प्रशासनिक सख्ती और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

पहली बारिश में बहा था स्टॉप डैम

धनपुरी क्षेत्र में निर्मित स्टॉप डैम का उद्देश्य जल संरक्षण और स्थानीय जलस्तर को बढ़ाना था, लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही बारिश में संरचना बह गई। इसके बाद निर्माण गुणवत्ता, तकनीकी स्वीकृतियों और निगरानी प्रक्रिया पर सवाल उठे। स्थानीय स्तर पर जांच की मांग उठी, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों या निर्माण एजेंसी के खिलाफ किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी है। इससे सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।

हादसे की जवाबदेही का सवाल

विशेषज्ञों के अनुसार बेसमेंट में अधिक भीड़ और व्यावसायिक गतिविधियां आग, धुआं या अन्य आपात स्थिति में गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। ऐसे स्थानों पर निकासी और सुरक्षा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होगा। प्रशासन ने मामले की दोबारा समीक्षा और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची स्विट्जरलैंड की टीम

पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से कोलंबिया को दी करारी शिकस्त

वैंकूवर , एजेंसी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने रोमांचक मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमों के बीच कोई भी गोल नहीं हो सका, जिसके बाद मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। इसमें रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड की जीत सुनिश्चित कर दी।

इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने इतिहास रच दिया। टीम 1954 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। 1954 में स्विट्जरलैंड ने मेजबानी करते हुए अंतिम-8 में जगह बनाई थी। अब 72 साल बाद टीम ने फिर से यह उपलब्धि हासिल की है।

अब अर्जेंटीना से होगी टक्कर

क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का सामना गत चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। यह मुकाबला शनिवार को अमेरिका के कैनसस सिटी स्थित एरोहेड स्टेडियम में खेला जाएगा। अर्जेंटीना ने अपने प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिस्र को 3-2 से हराकर अंतिम-8 में प्रवेश किया था।

अहम खिलाड़ी की गैरमौजूदगी के बावजूद मिली जीत

स्विट्जरलैंड इस मुकाबले में अपने युवा मिडफील्डर जोहान मन्जाम्बी के बिना उतरा था। मन्जाम्बी सोमवार को अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे और इस कारण मैच नहीं खेल सके। इसके बावजूद स्विस टीम ने शानदार अनुशासन और मजबूत रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए कोलंबिया को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया और अंत में पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर ली।

अर्श से फर्श पर वर्ल्ड चैंपियन

इंग्लैंड के मैदान पर आखिरकार वही हो गया ,जिसका अंदेशा आयरलैंड दौरे के आगाज में नजर आ गया था।इंग्लैंड के खिलाफ खेले गये तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया को टी20 प्रारूप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है।इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में टीम इंडिया की पारी महज 76 रनों पर ढेर हो गई।हार की वजह जो भी हो लेकिन एकादश के चयन से तो अब ऐसा लगता है जैसे टीम इंडिया में म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा हो,इतना ही नहीं अलग अलग दौरों के टीम चयन में भी चयनकर्ताओं का यही फार्मूला नजर आता है।दरअसल कौनसे दिग्गज की कब, कैसे और किस तरह टीम से विदाई तय कर दी जाती है यह कोई नहीं जानता है।सच तो यह है कि इन सभी का इस तरह की उठापटक का फार्मूला भी समझ से परे होता है। भले ही कई दिग्गज कप्तानों के लिए उम्र की दलील देते हुए दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है,लेकिन अगर शुभमन गिल जैसे ऑल फ़ॉर्मेट युवा खिलाड़ी के लिए चयनकर्ताओं का अबूझ फार्मूला यही होगा तो इस तरह के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे ही।मतलब साफ है कि विदेशी सरजमीं पर इस तरह की शिकस्त कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे नजरिये सबसे पहले चयनकर्ता ओर फिर टीम मैनजेमेंट का अड़ियल रवैया बेपटरी हुई टीम इंडिया असल जिम्मेदार है।8 मार्च 2026 को टी 20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने वाली टीम इंडिया यकायक जीत की पटरी से उतर गयी है।युवाओं के जोश से भरी युवा वर्ल्ड चैंपियन टीम के सभी धमाकेदार बल्लेबाजों ने 2 माह चले आईपीएल में भी वही कारनामा किया जिसकी बदौलत टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी।पूरे आईपीएल में जिस तरह की तूफ़ानी बल्लेबाजी भारतीय खिलाडियों ने की उसके बाद तो तरह तरह की बातें भी निकल कर आने लगी थी।देश ही नही विदेश के भी क्रिकेट पंडित यहां तक बोलने लगे थे कि इस फ़ॉर्मेट में भारत में टैलेंट की भरमार नजर आती है इसी वजह से बोर्ड 4 तटस्थ विश्व स्तरीय टीमें तैयार कर सकता है।बातें तो इससे भी अधिक की जाने लगी थी,लेकिन आईपीएल खत्म होने के बाद जैसे ही सितारों से सजी हुई चैंपियन टीम इंडिया विदेशी सरजमीं पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फ़ॉर्मेट में अपनी धाक साबित करने मैदान पर उतरी तो सभी के गुणगान उलटे नजर आये।दरअसल वर्ल्ड रैंकिंग की नंबर 2 टीम इंग्लैंड के खिलाफ उसकी जमीन पर उतरने के पहले टीम इंडिया का जो हश्र आयरलैंड के मैदानों पर हुआ उसके बाद से ही चैंपियन टीम के लिए लगाए गए तमाम पूर्वानुमान और उसके पैमाने ही अलग हो गए ।अगर हम वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया और विदेशी जमीन पर पिट रही टीम की बात करें तो फर्क सिर्फ बुमराह व हार्दिक पांड्या का ही कहा जा सकता है,लेकिन जब बात 4 समकक्ष टीमों के विश्व स्तरीय आकलन की हो रही हो तो फिर इन 2 खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी का असर चैंपियंस पर क्यों दिख रहा है।भले ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं और टीम मैनजेमेंट टीम में तरह तरह के प्रयोग कर टीम की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने का दावा ठोक रहा हो।टीम इंडिया के चयन का फार्मूला क्या है यह तो वही समझ सकते है। फिर भीऐसा लगता है कि चयनकर्ताओं ने टीम के चयन में अब सिर्फ चौक्के,छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर ही भरोसा है।जिसके एवज में उन्होंने बल्लेबाजी क्रम के लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन को भी ताक पर रख दिया है।चयनकर्ताओं ने टीम के चयन में जहाँ चौक्के,छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर ही भरोसा जताया,जिसके एवज में उन्होंने बल्लेबाजी क्रम के लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन को भी ताक पर रख दिया है।पहले 2 फ़ॉर्मेट के युवा कप्तान गिल फिर वर्ल्ड चैंपियन कटान सूर्यकुमार और अब वर्ल्ड कप चैंपियन खिलाड़ी सैमसन की दरकिनारी तो कुछ यही जताती है।जो भी हो पर सच तो यही है कि इन सभी की सोच असल वर्ल्ड चैंपियन यानी सभी हालातों की चैंपियन वाली टीम बनाने की असलियत से कोसों दूर है।वैसे भी टी20 और वनडे की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया टेस्ट फ़ॉर्मेट में तो विश्व स्तर पर काफी पिछड़ चुकी है।वहीं अब अगर इन दो फ़ॉर्मेट में भी इसकी कमजोरी उभर कर आने लगेगी तो फिर क्या भारतीय खिलाड़ी और उसका बोर्ड सिर्फ आईपीएल की बादशाहत तक सिमट जायेगा।मतलब साफ है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और मैनजेमेंट को अगर वाकई टीम इंडिया को असल वर्ल्ड चैंपियन बनाना है तो उसको घरेलू क्रिकेट की तमाम उन बातों पर गौर करना पड़ेगा जिसका फायदा युवा खिलाड़ियों को विदेशी सरजमीं पर हो।सिर्फ आईपीएल और घरेलू पाटा पिचों और अलग डाइमेंशन वाले मैदानों के भरोसे युवा खिलाड़ियों का पैमाना तय करना कितना घातक हो सकता है यह मौजूदा दौरे में साफ दिख रहा है।भले ही टी20 फॉर्मेट में बल्ले के धूमधड़ाके को अहमियत दी जाती है,लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ छक्कों की बदौलत ही सभी मुकाबले जीते जा सकते हों।वैसे भी जब विकेट सपाट न हो और मैदान के डाइमेंशन अलग और साइज बदले हुए मिलेंगे तो फिर जीत के फार्मूले ओर गणित भी अलग होते हैं।अगर हम बात मौजूदा दौरे में गयी टीम इंडिया की करें तो चैंपियन टीम को अर्श से फर्श पर आने की वजह इन्ही बातों को दरकिनार करना साफ नजर आ रहा है।

आलोक गोस्वामी
खेल विश्लेषक

एशिया कप की तारीख आई सामने,

अबकी बार वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा टूर्नामेंट, बांग्लादेश को मिली मेजबानी

नई दिल्ली, एजेंसी

एशिया कप 2027 की मेजबानी के लिए बांग्लादेश ने मीरपुर, सिलहट और चटगांव को संभावित वेन्यू के रूप में प्रस्तावित किया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंतिम फैसला लेने से पहले इन तीनों मैदानों की सुविधाओं और तैयारियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप 2027 वनडे फॉर्मेट में होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 18 जून से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 4 जुलाई को खेला जाएगा। हालांकि, बीसीबी ने अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

मीडिया से बातचीत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सईद इब्राहिम अहमद ने बताया कि बोर्ड ने देश के तीन नियमित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, मीरपुर, चट्टोग्राम और सिलहट को टूर्नामेंट के लिए प्रस्तावित किया है।

उन्होंने कहा, हम मीरपुर, चटगांव और सिलहट पर विचार कर रहे हैं क्योंकि यही हमारे नियमित अंतरराष्ट्रीय वेन्यू हैं। हालांकि अभी कुछ भी अंतिम नहीं हुआ है। अगर अगले साल एशिया कप बांग्लादेश में आयोजित होता है, तो दर्शकों को शानदार क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। अहमद ने बताया कि एसीसी ने बीसीबी से इन तीनों प्रस्तावित वेन्यू की सुविधाओं और अन्य तैयारियों के बारे में अधिक जानकारी मांगी है।

नॉटिंघम में भारतीय बल्लेबाजों का सरेंडर, मिली सबसे बड़ी शर्मनाक हार

अपने दूसरे न्यूनतम स्कोर पर ऑलआउट हुई टीम

नाटिंघम, एजेंसी

इंग्लैंड ने भारत को तीसरे टी20 मुकाबले में 125 रनों के बड़े अंतर से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत की इस प्रारूप में रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी हार है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत की बल्लेबाजी इस कदर खराब रही कि टीम के सिर्फ चार बल्लेबाज दहाई अंक तक पहुंच सके, लेकिन कोई भी 13 रन से ज्यादा नहीं बना पाया।

भारत को पहली बार टी20 में 100+ रनों के अंतर से हार मिली है। इससे पहले टीम को इस प्रारूप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी। 2019 में वेलिंगटन में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 80 रनों के अंतर से हराया था। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका ने 2026 में टीम इंडिया को 76 रनों से हराया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत अब तक एक भी मैच नहीं जीत सका है। पहले उसे आयरलैंड ने 0-2 से हराया और अब इंग्लैंड ने सीरीज में बढ़त बना ली है। इस सीरीज के दो मैच शेष हैं यानी भारत अब यहां से सीरीज अपने नाम नहीं कर सकता। ऐसे में अब उसकी कोशिश बराबरी करने की होगी।

टी20 में लगातार पांच मैचों से नहीं जीत सकी

भारत के लिए ब्रिटेन दौरा बेहद निराशाजनक रहा है। टीम पहली बार टी20 में लगातार पांच मैचों से जीत नहीं दर्ज कर सकी है। टीम को चार हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इससे पहले जून से दिसंबर 2009 तक और जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 तक टी20 में लगातार चार हार का सामना करना पड़ा था। श्रेयस की कप्तानी में भारत लगातार चार मैच हार चुका है। इंग्लैंड के साथ उसका पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। दोनों टीमों के बीच अब चौथा मुकाबला गुरुवार को ब्रिस्टल में खेला जाएगा।

मनोरंजन | **बॉलीवुड का कोना**

ड्रीम गर्ल के नाम पद्मिनी का भावुक संदेश

हेमा मालिनी को बताया यादों और प्रेरणा का अनमोल चेहरा

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी के प्रति अपना सम्मान और स्नेह व्यक्त करते हुए एक भावुक संदेश साझा किया है। सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट में उन्होंने हेमा मालिनी के लंबे फिल्मी सफर, यादगार किरदारों और भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान की दिल खोलकर सराहना की। पद्मिनी ने कहा कि हेमा मालिनी केवल ड्रीम गर्ल नहीं हैं, बल्कि वह ऐसी शख्सियत हैं जिनकी फिल्मों और अभिनय के साथ कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं।

पद्मिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कार्यक्रम का वीडियो साझा किया, जिसमें वह मंच पर हेमा मालिनी को गले लगाती नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा कि सीता और गीता की निडरता, शोले की मुस्कान और खुशबू की संवेदनशीलता जैसी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली है। उन्होंने लिखा कि हेमा मालिनी ने अपने अभिनय से सिनेमा को ऐसा अपनापन दिया, जिसे दर्शक आज भी महसूस करते हैं। कार्यक्रम के दौरान पद्मिनी ने हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और उनके पूरे परिवार से जुड़ी अपनी कई पुरानी यादों को साझा किया। उन्होंने कहा कि इस परिवार से उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा खास रहा है और उन्हें सभी से बेहद स्नेह मिला। इस अवसर पर पद्मिनी ने एक गीत भी प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

10 जुलाई को होगा विशेष सम्मान समारोह

मुंबई में 10 जुलाई को आयोजित होने वाला विशेष चैरिटी कॉन्सर्ट हेमा मालिनी के भारतीय सिनेमा में 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में धर्मेंद्र के फिल्मी योगदान को भी सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा। कार्यक्रम का निर्माण, निर्देशन और संचालन रेडियो होस्ट एवं लेखक अनिरुद्ध चावला करेंगे। इस विशेष शाम में फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। समारोह के दौरान जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश रोशन, रमेश सिप्पी, सुभाष घई, जावेद अख्तर, उमेश मेहरा, संजय खान और आनंदजी वीरजी शाह जैसी नामचीन हस्तियों को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर और उसके सितारों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ नई पीढ़ी को उनकी विरासत से परिचित कराने का भी एक विशेष अवसर माना जा रहा है।

थूक-थूक कर बिगाड़ा एक्ट्रेस का चेहरा, पोस्टर का वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल!

एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है। वीडियो में टूथपेस्ट ब्रांड के एक पोस्टर पर पान की पीक थूकी हुई नजर आती है। इस पोस्टर में एक्ट्रेस, राइटर और डायरेक्टर दिव्या उन्नी का चेहरा है। वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वहीं दिव्या ने भी अपना रिएक्शन दिया। दिव्या उन्नी ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। लेकिन उनका जवाब सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इसे समाज में महिलाओं के प्रति सोच से जोड़ दिया।

दिव्या ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कई लोग उन्हें वायरल क्लिप भेज रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस दीवार पर उनका पोस्टर लगा था, उसी पर कई पुरुष नेताओं के पोस्टर भी लगे थे, लेकिन पान की पीक सिर्फ महिला के चेहरे पर थूकी गई। दिव्या ने कहा- वहां पोस्टर पर मैं दिव्या उन्नी नहीं हूं, वो सिर्फ एक औरत का चेहरा है। वो किसी भी महिला का चेहरा हो सकता था। मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लूंगी कि किसी ने दिव्या उन्नी के चेहरे पर थूका है।

एक्ट्रेस ने माना कि ये घटना उन्हें परेशान जरूर कर गई, लेकिन उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के साथ जो हिंसा और अपमान होता है, उसके सामने ये घटना बहुत छोटी है। उन्होंने कहा- ये बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन क्या ये कोई नई बात है? हमारे देश में ज्यादातर पुरुष महिलाओं का सम्मान नहीं करते। वो महिलाओं के नजरिए को समझना ही नहीं चाहते। कई लोग तो महिलाओं को इंसान तक नहीं समझते। दिव्या ने कहा कि वो इस मानसिकता के खिलाफ अपनी तरह से लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने बताया कि वो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, हिंसा और भेदभाव जैसे मुद्दों पर फिल्में बनाना चाहती हैं ताकि लोगों की सोच बदली जा सके।

मेट्रो बाजार

2026 में एक दिन में सबसे ज्यादा एसएमई आईपीओ की हुई लिस्टिंग, 6 कंपनियों ने बाजार में मारी एंट्री

मुंबई । भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार का कारोबारी सत्र ऐतिहासिक रहा। इस दौरान कुल 6 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज (एसएमई) कंपनियों की लिस्टिंग हुई, जो कि 2026 में एसएमई आईपीओ लिस्टिंग का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लिस्ट हुई छह एमएमई कंपनियों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए संयुक्त रूप से 185.14 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इनमें से दो कंपनियों की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एसएमई प्लेटफॉर्म एनएसई इमर्ज पर हुई, जबकि बाकी चार कंपनियों की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के एसएमई प्लेटफॉर्म बीएसई एसएमई पर हुई। इससे पहले 24 जून को एक साथ चार एसएमई कंपनियों की शेयर बाजार में एंट्री हुई थी। इन सभी कंपनियों ने मिलकर शेयर बाजार से 252.55 करोड़ रुपए जुटाए।

एसएमई आईपीओ उन छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों का आईपीओ होता है, जिनका कारोबार और पूंजी मेनबोर्ड कंपनियों की तुलना में छोटा होता है। ये कंपनियां मुख्य रूप से एनएसई के इमर्ज और बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध होती हैं। मेनबोर्ड आईपीओ की तुलना में एसएमई आईपीओ में न्यूनतम निवेश राशि अधिक होती है और लॉट साइज भी बड़ा होता है। साथ ही, इनमें तरलता अपेक्षाकृत कम और जोखिम अधिक माना जाता है, क्योंकि कंपनियों का आकार छोटा तथा कारोबार सीमित होता है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती से देश की आर्थिक रफ्तार को मिल रही मदद : रिपोर्ट

नई दिल्ली । मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से देश की आर्थिक रफ्तार को अप्रैल-मई के दौरान कम होने से रोकने में मदद मिली है। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है और निर्यात और इन्वेंट्री बढ़ाने की वजह से इसने मुश्किल हालात में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि एनर्जी मार्केट में अनिश्चितता के कारण एहतियात के तौर पर इन्वेंट्री बढ़ाई गई। इससे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा हुआ। यह ट्रेंड खासकर कंज्यूमर गुड्स में देखा गया। वहीं, यूएस में कम टैरिफ की वजह से संभावित %सेक्शन 301 टैरिफ% से पहले गैर-तेल निर्यात को बढ़ाने का मौका मिला। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 ग्रोथ इंडिकेटर्स का डेटाबेस अप्रैल-मई में सुस्त पड़ती रफ्तार की ओर इशारा करता है। साथ ही, बहुत मजबूत अल-नीनो और कमजोर मानसून की आशंका से खेती और ग्रामीण मांग पर जोखिम मंडरा रहा है। बैंक ने बताया कि भारतीय कंपनियों को कम टैरिफ के चलते अमेरिका में %सेक्शन 301% के संभावित उपायों से पहले गैर-तेल निर्यात बढ़ाने का मौका मिला, जिससे फैक्ट्री की गतिविधियों को बढ़ावा मिला। हालांकि, रिपोर्ट में खेती के अलावा ग्रोथ के लिए दो सकारात्मक कारकों पर जोर दिया गया, खासकर सर्विस सेक्टर में, जो जीडीपी का 55 प्रतिशत हिस्सा है। तेल की कीमतों का युद्ध से पहले के स्तर पर वापस आना व्यापार और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है, जो जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है। साथ ही, एफएक्स पैकेज की वजह से आसान फाइनेंशियल स्थितियों से फाइनेंशियल सेक्टर को गति मिल सकती है, जो जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत है।

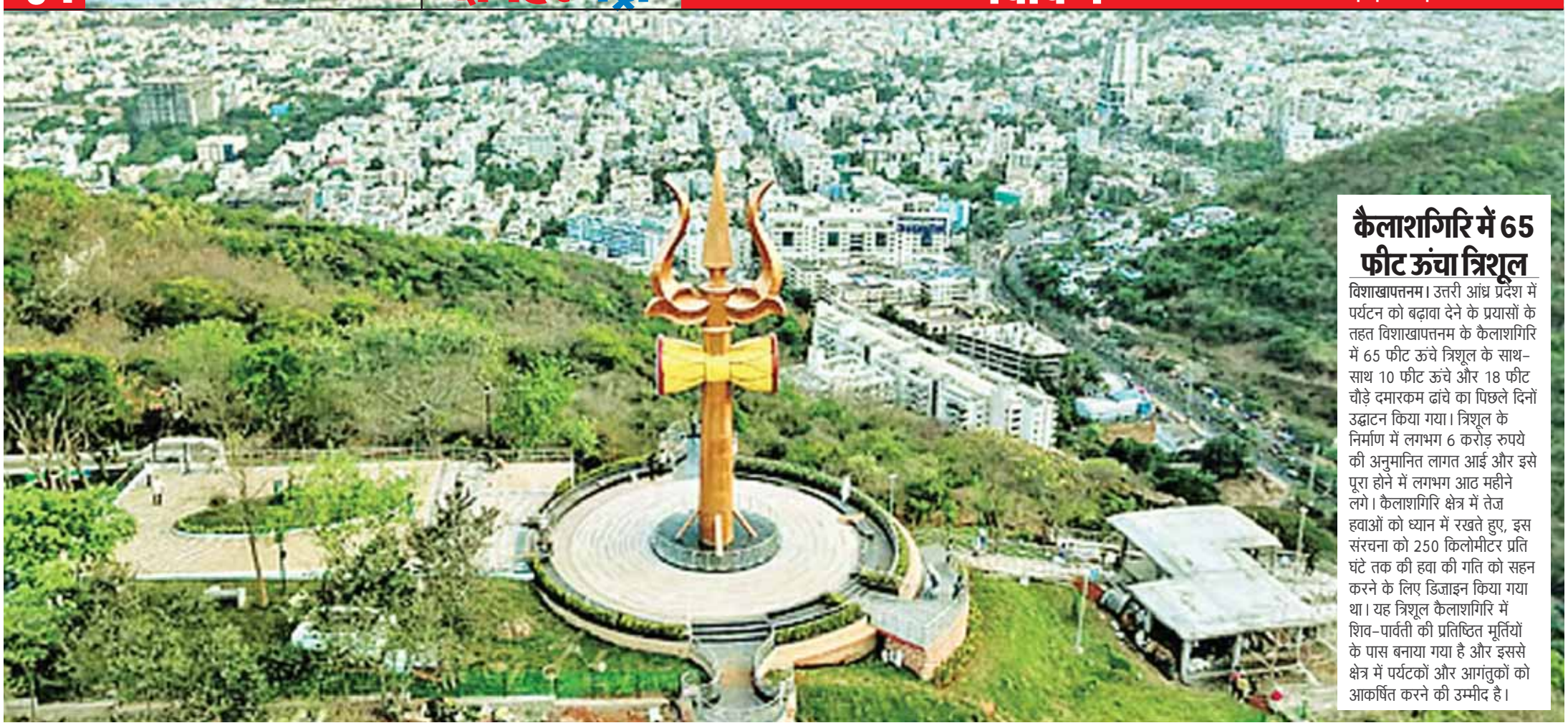

कैलाशगिरि में 65 फीट ऊंचा त्रिशूल

विशाखापत्तनम। उत्तरी आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत विशाखापत्तनम के कैलाशगिरि में 65 फीट ऊंचे त्रिशूल के साथ-साथ 10 फीट ऊंचे और 18 फीट चौड़े दमारकम ढांचे का पिछले दिनों उद्घाटन किया गया। त्रिशूल के निर्माण में लगभग 6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आई और इसे पूरा होने में लगभग आठ महीने लगे। कैलाशगिरि क्षेत्र में तेज़ हवाओं को ध्यान में रखते हुए, इस संरचना को 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह त्रिशूल कैलाशगिरि में शिव-पार्वती की प्रतिष्ठित मूर्तियों के पास बनाया गया है और इससे क्षेत्र में पर्यटकों और आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है।

न्यूज विंडो

युवाओं को लत लगाने में मेटा से मांगा 1.4 खरब डॉलर का जुर्माना

कैलिफोर्निया। अमेरिका के चार प्रांत कंपनी पर 1.4 खरब डॉलर का जुर्माना लगाने की मांग कर रहे हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया है कि युवा यूजर्स इसकी लत लगा बैठें और उनकी सुरक्षा के बारे में जनता को गुमराह किया। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अदालत में यह आंकड़ा अटॉर्नी जनरल की उन फाइलिंग के जवाब में पेश किया, जिनमें कह था कि यदि राज्य ट्रायल जीतते हैं तो जुर्माने की गणना कैसे होनी चाहिए। इस आंकड़े का खुलासा पहले कभी नहीं हुआ।

यह मेटा के 1.5 खरब डॉलर की बाजार पूंजी के करीब है। ये दावे कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यूजर्सी में हुए हैं। मेटा ने कहा, यह रकम सबूतों पर आधारित नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण के इतिहास में ऐसे दण्ड का कोई उदाहरण नहीं है। फाइलिंग के बाद अटॉर्नी जनरल के प्रतिनिधियों ने कोई टिप्पणी नहीं की। राज्यों ने कहा कि उल्लंघनों की संख्या मेटा की गतिविधियों से प्रभावित किशोरों और युवा यूजर्स की अनुमानित संख्या पर आधारित है।

बस स्टैंड पर टवेरा ने लोगों को रौंदा, 200 मीटर तक घसीटा, कई घायल

छिंदवाड़ा। पीपला नारायणवार नगर के बस स्टैंड क्षेत्र में सुबह तब अफरा तफरी मच गई जब बजाज मार्ग की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार टवेरा अचानक अनियंत्रित होकर 3-4 दुकानों में घुस गई।हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों में चीख-पुकार मच गई।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टवेरा की चपेट में आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं, सड़क किनारे खड़े कई दोपहिया वाहन भी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए।स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को वाहन से बाहर निकाला और उपचार के लिए सौसर अस्पताल पहुंचाया। यहां कुछ घायलों को गंभीर हालत होने पर नागपुर रेफर किया गया है।

पाकिस्तान के शारजाह से कराची जा रहा कार्गो विमान लापता

लाहौर। पाकिस्तान में मंगलवार रात को शारजाह से कराजी जा रहे बोइंग 737 मालवाहक विमान का हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया। विमान के पायलट ने पहले नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी थी। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। विमान में पांच चालक दल के सदस्य सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि के2 एयरवेज द्वारा संचालित 27 साल पुराने परिवर्तित मालवाहक विमान ने कराची की ओर उड़ान भरते समय पाकिस्तानी मानक समय के अनुसार रात 9:18 बजे नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना दी।अधिकारियों के अनुसार, समस्या की सूचना मिलने के बाद स्थानीय हवाई यातायात नियंत्रकों ने विमान को निर्देशित करने का प्रयास किया। हालांकि, रडार सिस्टम ने लगभग तीन मिनट बाद विमान को तेजी से नीचे उतरते हुए दिखाया और विमान से संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि उस समय विमान कराची से लगभग 155 समुद्री मील (287 किमी) पश्चिम में था।

सवालों के घेरे में एमपी कांग्रेस की एकजुटता

दिग्विजय की पटवारी से दूरी और उमंग से नजदीकी...नए समीकरण के संकेत

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव हैं। जब कांग्रेस को एक होकर मैदान में उतरना चाहिए, तब भी पार्टी अलग-अलग पॉवर सेंटर में बंटी नजर आ रही है। कांग्रेस की एकजुटता की कमी एक बार फिर उज्जैन में वीर भारत न्यास को जमीन देने के आरोपों पर खुलकर सामने आई थी। प्रदेश अध्यक्ष और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के बीच बयानबाजी और उसके बाद कांग्रेस के भीतर ही खिलाफत की खबरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच हुई बंद कमरे में लंबी बातचीत से नई सियासी समीकरणों को हवा मिल रही है।

लगभग दो दशक से सत्ता से बाहर चल रही मध्यप्रदेश कांग्रेस आज भी अंदरूनी खींचतान से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के रूप में कांग्रेस ने नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपा है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव अभी भी कायम है। इसी बीच उमंग सिंघार का अचानक दिग्विजय सिंह के निवास पहुंचना और दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे तक बंद कमरे में चर्चा होना कई सवाल छोड़ गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर कांग्रेस के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत? ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार के रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे हैं। वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर सरकार में हस्तक्षेप और पर्दे के पीछे से फैसले लेने जैसे आरोप लगाए थे। उस समय दोनों नेताओं के बीच खुलकर बयानबाजी भी हुई थी।

नई और पुरानी पीढ़ी के बीच तालमेल बड़ी चुनौती

कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे दोनों अहम पद नई पीढ़ी के नेताओं को सौंपे हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को राहुल गांधी की टीम का करीबी माना जाता है। वहीं दिग्विजय सिंह लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। कमलनाथ की प्रदेश में सक्रियता पहले की तुलना में काफी कम हुई है। उनका अधिकांश समय अब छिंदवाड़ा तक सीमित रहता है। इसके विपरीत दिग्विजय सिंह लगातार प्रदेशभर में सक्रिय हैं और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। ऐसे में नई और पुरानी पीढ़ी के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना कांग्रेस नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

विवाद के बाद बढ़ी हलचल

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर पार्टी असहज स्थिति में नजर आई थी। जीतू पटवारी ने उज्जैन में सरकारी जमीन आवंटन को लेकर भाजपा सरकार पर 500 करोड़ रुपये की जमीन एक रुपये में देने का आरोप लगाया था। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि संबंधित जमीन सरकारी ट्रस्ट की है और उसे निजी संस्था को नहीं दिया गया। भाजपा ने इसे कांग्रेस के अंदर की लड़ाई बताकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया।

सब ठीक नहीं वाली बात फिर उठी

यूं तो कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा हावी रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ समेत कई नेता सीमित दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला उज्जैन स्थित वीर भारत न्यास को जमीन आवंटन के आरोपों पर सामने आया। पटवारी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन मात्र एक रुपये में वीर भारत न्यास के सचिव और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी से जुड़े एक ट्रस्ट को आवंटित कर दी। उन्होंने इस मामले में सरकार पर पक्षपात और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

धनबाद के छाताबाद में जमीन फटी, आधा दर्जन घर ध्वस्त

कतरास(धनबाद)। धनबाद के कतरास के छाताबाद चार नंबर में सुबह हुए अचानक जोरदार आवाज के साथ हुई भू-धंसान से आधा दर्जन से अधिक घर जमींदोज हो गए, जबकि एक दर्जन से अधिक घरों में दरारें पड़ने से इलाके में दहशत फैल गई। घटना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के गोविंदपुर क्षेत्र की न्यू आकाशकिनारी कोलियरी के परियोजना के समीप हुई।

सुबह करीब आठ बजे तेज धमाके जैसी आवाज के साथ जमीन धंसने लगी और देखते ही देखते कई घर धराशायी हो गए। लोग जान बचाकर घरों से बाहर भागे। किसी ने बच्चों को सीने से लगाकर तो किसी ने बुजुर्गों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान की ओर पहुंचाया। बगल के एक बड़ा तालाब का पानी भी जमीन में समा गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद प्रभावित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आस पड़ोस के हजारों लोग भी भय और दहशत में आ गए। आक्रोशित ग्रामीणों सहित भू-धंसान प्रभावित परिवारों ने कतरास-भटमुरना मुख्य सड़क जाम कर दिया।

यूएस में सतिंदरजीत सिंह पर 50 हजार डॉलर का इनाम, लॉरेंस से तार जुड़े होने के आरोप

वाशिंगटन। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह, उर्फ 'गोल्डी बरार' की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर तक के इनाम की घोषणा की। गोल्डी बरार पर लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप में शामिल होने का आरोप है और वह कई मामलों में वांछित है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में इनाम की घोषणा करते हुए, संघीय जांच एजेंसी ने कहा, 'सतिंदरजीत सिंह की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 50,000 डॉलर तक का इनाम दे रही है।

सिंह लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप में कथित तौर पर शामिल होने के कारण वांछित है। यह ग्रुप दक्षिणी कैलिफोर्निया और पूरे अमेरिका और कनाडा में कई हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है।' गोल्डी बरार अमेरिका में रहता है और कथित तौर पर उत्तरी अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप के कामकाज का लीडर है।

नौकरी के 27 दिन बाद ही चढ़ावा साफ करने लगा मनीष

राममंदिर चोरी मामला: अन्य आरोपियों के राज खुलना अभी भी बाकी

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस टिन्नू का नाम आते ही ट्रस्ट महासचिव चंपतराय तक घिर गये थे, साथ ही उन पर तरह-तरह के आरोप लगने लगे थे, उस टिन्नू का भतीजा तो उससे भी तेज निकला।

टिन्नू बिना औपचारिक आदेश के हुंडियों की चाभी रखता था तो उधर उसका भतीजा मनीष गणना कक्ष में नौकरी शुरू करने के मात्र 27 दिन बाद ही चढ़ावे की धनराशि पर हाथ साफ करने लगा। उस अनुकल्प गैंग से जुड गया, जो चढ़ावा चोरी का मास्टर माइंड था।एसआईटी रिपोर्ट में उल्लेख है कि 15 अप्रैल 2026 को मनीष गणना कक्ष में नौकरी करने लगा और 11 मई के बाद के कई सीसीटीवी फुटेजों में मनीष यादव धनराशि चोरी या गबन करता पाया गया।चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट महासचिव चंपतराय व ट्रस्टी डा. अनिल कुमार मिश्रा का भले ही त्यागपत्र हो गया और एसआईटी ने चंपतराय को क्लीन चिट दे दी, लेकिन एसआईटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट ने मंदिर में चढ़ने वाली धनराशि के रखरखाव से जुड़ी अव्यवस्थाओं की परतें खोल कर रख दी है।

मेट्रो एंकर — इसरो को मिली एक और बड़ी सफलता

एलवीएम-3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 के सातवें परिचालन मिशन के लिए निर्धारित सीई-20 क्रायोजेनिक इंजन का अंतिम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण में रॉकेट में लगाने से पहले इंजन को वास्तविक परिस्थितियों की तरह चलाकर यह परखा जाता है कि वह सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं।

इसरो ने जारी एक बयान में बताया कि यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। पहले जीएसएलवी एमके-3 के नाम से पहचाने जाने वाला एमवीएम-3 इसरो का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसके ऊपरी चरण को शक्ति देने के लिए सीई-20 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है।

अंतरिक्ष अभियानों में रॉकेट को लॉन्च करने से पहले उसके इंजन की वास्तविक उड़ान जैसी परिस्थितियों में जांच की जाती है। इस टेस्ट के जरिए यह परखा जाता है कि इंजन वास्तविक उड़ान के दौरान सही ढंग से काम करेगा या नहीं। इसरो ने बताया कि परीक्षण के दौरान इंजन की सभी प्रणालियों का प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक पाया गया है।

इसरो ने कहा, ''इंजन 19 टन से 22 टन तक के थ्रस्ट (रॉकेट या इंजन को आगे की ओर धकेलने की क्षमता) पर काम करने के लिए प्रमाणित है। यह इंजन अब तक एलवीएम-3 के लगातार आठ सफल मिशनों में शानदार प्रदर्शन कर चुका है। इनमें चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और तीन वाणिज्यिक मिशन भी शामिल हैं।

पहली बार 'नोजल सुरक्षा प्रणाली' का हुआ इस्तेमाल

इसरो ने कहा, ''गगनयान मिशन में इस्तेमाल के लिए इस इंजन ने मानव मिशनों के लिए आवश्यक सुरक्षा और विश्वसनीयता संबंधी सभी मानकों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।'' हाल ही में किए गए अंतिम उड़ान परीक्षण के दौरान सीई-20 इंजन का 22 टन थ्रस्ट पर परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में पहली बार 'नोजल सुरक्षा प्रणाली' (एनपीएस) का उपयोग किया गया। एनपीएस एक ऐसी तकनीक है, जो इंजन के नोजल (रॉकेट इंजन का नोजल वह हिस्सा होता है, जिससे अत्यधिक गर्म और तेज गति वाली गैसें बाहर निकलती हैं) को परीक्षण के दौरान सुरक्षित रखती है और विशेष रूप से उच्च ऊंचाई जैसी परिस्थितियों में इंजन का परीक्षण आसान बनाती है। इसरो के अनुसार, यह प्रणाली उच्च ऊंचाई जैसी परिस्थितियों में किए जाने वाले जटिल परीक्षणों को काफी आसान बनाती है। इसकी मदद से कम संसाधनों में परीक्षण किया जा सकता है और परीक्षण की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसरो ने कहा, ''परीक्षण के परिणामों से इंजन की सभी प्रणालियां और एनपीएस का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है।'

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक राजेश सिरोठिया द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा* आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) फोन : 0755-7963564